राष्ट्रीय संस्करण



सत्यम् लाइव



satyamlive@yahoo.com

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित एवं दिल्ली-एन.सी.आर सहित सम्पूर्ण भारत में प्रसारित

RNI: DELHIN/2011/36763

वर्ष : 16, अंक : 33, सोमवार, 12 अक्तूबर से 18 अक्तूबर, 2026 www.satyamlive.com साप्ताहिक, पृष्ठ : 08, सम्पादक : योगेश कुमार, मूल्य : 1.00 रु.

कौशल प्रशिक्षण संस्थान आईआईटी से कम नहीं: मोदी

भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी और उन्हें देश में कौशल विकास का दूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

योगेश कुमार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कौशल प्रशिक्षण संस्थानों का महत्व किसी भी तरह से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) से कम नहीं है। उन्होंने युवाओं से बदलती तकनीक के अनुरूप लगातार नए कौशल सीखने और अपनी क्षमताओं को उन्नत करने का आह्वान किया। मोदी ने यहां अपने आवास सात, लोक कल्याण मार्ग पर शंघाई में आयोजित 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीम के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी और उन्हें देश में कौशल विकास का दूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यावहारिक कौशल भी शैक्षणिक डिग्रियों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने युवाओं से अंतरराष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित करने और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने को कहा। भारत को कुशल मानव संसाधन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए युवाओं, सरकार और प्रशिक्षण संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रतियोगिता के दौरान प्राप्त अनुभव और सुझाव सरकार के साथ साझा करने का आग्रह किया,



ताकि देश की कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता के दौरान नए उपकरणों, सॉफ्टवेयर, तकनीकी प्रणालियों और कार्य प्रक्रियाओं के अनुरूप खुद को ढालने के अनुभव साझा किए। उन्होंने कौशल विकास के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक आयोजित 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत 10वें स्थान पर रहा। भारतीय दल ने छह रजत पदक और उत्कृष्टता के 20 पदक जीते। प्रतियोगिता में भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा 70 सदस्यीय दल 63 कौशल श्रेणियों में शामिल हुआ था। इस बातचीत में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री तथा शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

उपचुनाव: असम, बंगाल और पुदुचेरी में जीत पर पीएम मोदी ने जताया मतदाताओं का आभार

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में भाजपा-एनडीए उम्मीदवारों की जीत के बाद मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने के साथ पार्टी कार्यकताओं की मेहनत की भी सराहना की। मोदी ने कहा कि ये नतीजे भाजपा-एनडीए के सुशासन के एजेंडे के प्रति लोगों के जुड़ाव को दिखाते हैं। उन्होंने पुदुचेरी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी एआईएनआरसी को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोगों का समर्थन गठबंधन को और मजबूती देता है। उन्होंने असम के नगांव लोकसभा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम व रेजिनगर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों की जीत का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि इन नतीजों से पता चलता है कि लोग भाजपा-एनडीए के सुशासन के एजेंडे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकताओं की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों का भी इस जीत में महत्व है।

> भाजपा के विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूं और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की भी सराहना करता हूं। यह जनादेश हमें लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम करने और बेहतर व अधिक समृद्ध भविष्य के उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में अतिरिक्त ताकत देगा।
>
> *प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी*



एनडीए के सहयोगी दल को भी दी बधाई: मोदी ने पुदुचेरी के थट्टांचावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता का यह जनादेश लोगों के कल्याण के लिए काम करने और उनकी उम्मीदों को पूरा करने की ताकत देगा। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि गठबंधन लोगों के बेहतर और समृद्ध भविष्य के लिए लगातार काम करेगा।

चुनावी जीत पर अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जीत को लेकर राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार के बावजूद भाजपा को जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी के उपचुनावों के साथ राजस्थान और त्रिपुरा के हालिया निकाय चुनावों में एनडीए की जीत का भी जिक्र किया। अमित शाह ने दावा किया कि इन चुनावी नतीजों से पता चलता है कि जनता ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जनाधार खो चुके विपक्षी दल हर हार के बाद संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता उनके रवैये को पहचान चुकी है। शाह के मुताबिक, लोगों ने एक बार फिर प्रचंड जनादेश देकर भाजपा पर अपना अटूट विश्वास जताया है।

'स्वस्थ प्रदेश-सक्षम प्रदेश' बना यूपी: मुख्यमंत्री योगी



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'स्वस्थ-सक्षम उत्तर प्रदेश' की कहानी अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' के जरिए शुक्रवार को प्रदेशवासियों से साझा की। मुख्यमंत्री ने उपचार की विवशता से स्वास्थ्य सुरक्षा के विश्वास को स्वस्थ उत्तर प्रदेश की नई पहचान बताया।

वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज के साथ नए मानक स्थापित कर रहा यूपी: मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन और अंत्योदय के संकल्प के साथ प्रदेश की डबल इंजन भाजपा सरकार ने वर्ष 2017 से पहले की स्वास्थ्य क्षेत्र की लचर व्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक गति से कार्य किया है। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया से होती थी, वही उत्तर प्रदेश आज वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज के संकल्प के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है।

उपचार की सुविधा का लगातार विस्तार: मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां प्रदेश में वर्ष 2017 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 36 थी, वहीं आज यह बढ़कर 85 हो गई है। साथ ही, एमबीबीएस की सीटें 4,690 से बढ़कर 13,600 से अधिक हो चुकी हैं। इससे एक ओर युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर आमजन के लिए घर के निकट गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा का विस्तार हुआ है।

उपचार के खर्च की चिंता से मुक्त हैं प्रदेशवासी: मुख्यमंत्री ने लिखा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित 10 करोड़ से अधिक प्रदेशवासी आज गंभीर बीमारी के उपचार के भारी खर्च की चिंता से मुक्त होकर बेहतर स्वास्थ्य, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। उपचार की विवशता से स्वास्थ्य सुरक्षा के विश्वास तक, स्वस्थ उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है।



केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिरी ने नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक की तीन-खंडों वाली सीरीज "अरुणाचल: द सैप रन्स पेरिनियल" जारी की।

सीजेपी के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शन से पहले दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों और यातायात पर लगाई गई पाबंदियों पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन आम जनता की आवाजाही को ठप करने के लिए 'मक्खी मारने के लिए हथौड़े' जैसी अत्यधिक कड़े कदमों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है। इससे पहले दिल्ली में सख्त पाबंदियां लगाई गई है। इन कड़ी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। दिल्ली पुलिस द्वारा मेट्रो स्टेशनों को बंद करने, सड़कों पर बैरिकेडिंग और ट्रेनों की आवाजाही रोकने के कदमों पर सवाल उठाते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए आम जनता और यात्रियों की आवाजाही को पूरी तरह बाधित नहीं किया जा सकता।



सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि इस कदम से गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और शहर के दूसरे हिस्सों से दिल्ली आने वाले हजारों यात्रियों-जिनमें छात्र, कर्मचारी और बुजुर्ग शामिल हैं, उन पर असर पड़ता है। कोर्ट ने सरकार से बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों की संख्या कम करने और पाबंदियों की तत्काल समीक्षा करने को कहा है।

हर किसी के पास कार नहीं होती... सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "हर किसी के पास कार नहीं होती... आप सब कुछ रोक नहीं सकते और लोगों को परिवहन सुविधा के बिना नहीं छोड़ सकते।" सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सुनिश्चित करने को कहा कि 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली के लिए ट्रेन सेवाएं और मेट्रो संचालन पूरी तरह से निलंबित न किए जाएं। यात्रियों के लिए चिंता व्यक्त करते हुए, अदालत ने केंद्र से कहा कि सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग शहर के सभी हिस्सों से यात्रा करते हैं। कोर्ट ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि मेट्रो ट्रेनों के संचालन पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा।" मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अगर विरोध प्रदर्शन इजाजत के साथ किया जाता है, तो यह एक कानूनी विरोध प्रदर्शन है। भले ही यह पूरी तरह से कानून का पालन न करे, हम कभी यह नहीं कहते कि लोगों को विरोध करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, वे ऐसा अपने जोखिम पर करते हैं।' कोर्ट ने दिल्ली में लगी पाबंदियों का जिक्र करते हुए, संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। जस्टिस बागची ने कहा, 'अगर हम इस पर रोक लगाते हैं, तो हम संगठन पर भी रोक लगाएंगे, तो क्या यह सही होगा।

सरकार ने 455 लेखपालों को दी पदोन्नति

लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रदेश में राजस्व प्रशासन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड ने चयन वर्ष 2025-26 के तहत ऑनलाइन विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश के 455 लेखपालों को राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) के पद पर पदोन्नति प्रदान की है। पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड के चेयरमैन बीएल मीणा ने बताया कि पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई गई। निर्धारित पात्रता मानकों और सेवा अभिलेखों के आधार पर कार्मिकों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद 455 लेखपालों को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया।

भाजपा ने 2027 चुनाव के लिए कसी कमर, बांसुरी स्वराज ने दिया बूथ मजबूती का मंत्र

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने महानगर स्तर पर संगठन को चुनावी तैयारी के मोड में लाने के संकेत दिए हैं। भाजपा की उत्तराखंड सह-प्रभारी एवं सांसद बांसुरी स्वराज के महानगर के पहले दौरे में संगठन की प्राथमिकता साफ नजर आई। ""बूथ मजबूत करो, कार्यकताओं को सक्रिय करो और जनसंपर्क बढ़ाओ।"" महानगर भाजपा कार्यालय में आयोजित स्वागत व संवाद कार्यक्रम में उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकताओं के साथ चुनावी तैयारियों तथा संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। बांसुरी स्वराज ने कार्यकताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच लगातार सक्रिय

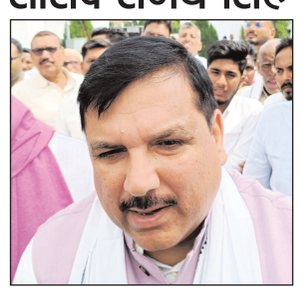


रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की मूल शक्ति हैं।

आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी भूमिका सक्रियता से निभानी होगी। बूथ पर प्रभावी उपस्थिति, कार्यकताओं के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर जनसंपर्क को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। कार्यकताओं से सेवा, समर्पण व संगठन की भावना के साथ जनसेवा में जुटे रहने का आह्वान करते हुए उन्होंने ""सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास"" के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बांसुरी स्वराज ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत संवाद किया। इस दौरान कार्यकताओं के बीच समन्वय, बूथ स्तर की सक्रियता और जनता के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई।

मुख्य चुनाव आयुक्त का जेल जाना जरूरी : राज्यसभा सांसद संजय सिंह

बलिया। आम आदमी पार्टी (आआप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर ज्ञानेश कुमार के जरिए वोट चोरी करवाने का आरोप लगाया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्व. रामगोविन्द चौधरी की तेरहवीं संस्कार में शुक्रवार को गोसाईंपुर पहुंचे संजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि अभी हाल ही में यूपी में तेरह लाख वोट बढ़ा दिये गए, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। इसी तरह बिना कारण 65 हजार वोट काट दिए गए। देश और प्रदेश में यह क्या चल रहा है। यह चुनाव है या मजाक। यूपी में तो अभी तीन महीने बाद चुनाव होने हैं। इन तीन महीनों में ये लोग क्या-क्या खेल



करेंगे। अगर इसी तरह चुनाव होगा तो बाकी उन पार्टियों का क्या हश्र होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार को जेल होना चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा सीजेपी के प्रदर्शन को समर्थन देने के सवाल पर कहा कि हम भी वोट चोरी के सवाल पर सीजेपी के साथ हैं। मैं ये मानता हूं कि हर वो पार्टी सीजेपी के साथ हैं जो यह मानती हैं कि देश में वोट चोरी हो रहा है।

दिल्ली में 34 आईएएस, दानिक्स अधिकारियों के तबादले

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स) के 34 अधिकारियों के तबादले कर दिये हैं। दिल्ली सरकार के कार्मिक विभाग ने उपराज्यपाल की मंजूरी से दिनांक 8 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत 34 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त विभागों का प्रभार सौंपा गया है, जबकि कुछ अधिकारियों के मौजूदा दायित्वों में बदलाव किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश के अनुसार, 1992 बैच के आईएएस अधिकारी बिपुल पाठक को अतिरिक्त मुख्य सचिव (समाज कल्याण) के साथ दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम, दिल्ली



अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें वित्त आयुक्त की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

वहीं, 1993 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशांत गोयल को अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) के साथ दिल्ली वित्त निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, प्रशासनिक सुधार विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी को सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनके पास सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का भी प्रभार रहेगा।

आईएएस अधिकारी दिलराज कौर से दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम और दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। वह शिक्षा तथा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव बनी रहेंगी। निहारिका राय को परिवहन सचिव-सह-आयुक्त के साथ दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। उनसे पर्यटन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया है। रूपेश कुमार ठाकुर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव पद से हटाकर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

गुजरात के कच्छ में ट्रक और बोलेरो के बीच टक्कर में सात मजदूरों की मौत

भुज/अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ में आज सुबह ट्रक और बोलेरो के बीच टक्कर में सात मजदूरों की मौत हो गई। बोलेरो गाड़ी में 15 से ज्यादा मजदूर सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि केबिन में फंसे लोग दर्द से कराह रहे थे। वहां आसपास मौजूद लोग यह मंजर देख आवाक थे। कच्छ जिले में आज मजदूरों को ले जा रही एक बोलेरो गाड़ी खावड़ा के पास आरई पार्क के रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में सात मजदूरों की मौत हो गई। बोलेरो में 15 से ज्यादा मजदूर सवार थे, जबकि कुछ घायल हो गए हैं।

आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल में गैस लीक होने से लगी आग, पांच झुलसे

मुंबई। मुंबई के पवई इलाके में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी बॉम्बे) के हॉस्टल नंबर-६ में बीती रात गैस सिलेंडर की पाइप से गैस लीक होने के कारण आग लग गई। इस घटना में दो बच्चों समेत पांच लोग झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पवई पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि बीती रात आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल नंबर-६ में गैस सिलेंडर की पाइप से गैस का रिसाव हुआ। इसके बाद अचानक आग लग गई, जिससे आसपास मौजूद पांच लोग इसकी चपेट में आकर



घायल हो गए। इस घटना में अंश अहिरवार (१२), तहजीब आलम (९), ईश्वर सिंह (३७), शिवकुमार सिंह (३४) और अनिलकुमार यादव (२३) झुलस गए। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। इनमें से चार लोगों को आगे के इलाज के लिए कस्तूरबा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि एक का राजावाड़ी अस्पताल में उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार, सभी की हालत फिलहाल स्थिर है। आज सुबह आग पर काबू पा लिया है। मौके पर कूलिंग काम जारी है। फिलहाल, गैस रिसाव के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है।

संपादकीय

महँगाई की आग और रेपो रेट का ब्रेक

मौद्रिक नीति का यह औजार मांग को नियंत्रित कर कीमतों पर दबाव घटाता है, पर भारत जैसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ईंधन की महँगाई से निपटने के लिए आपूर्ति-पक्ष के उपाय भी जरूरी महँगाई किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए केवल बढ़ती कीमतों का सवाल नहीं है, बल्कि यह आम नागरिक की क्रयशक्ति, बचत, निवेश और जीवन-स्तर को सीधे प्रभावित करती है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो समान आय में परिवार पहले की तुलना में कम वस्तुएँ खरीद पाते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की होती है। इसी उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर रेपो रेट में बदलाव करता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उपलब्ध कराता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक से धन लेना महँगा हो जाता है। इसका असर धीरे-धीरे बैंक ऋण की ब्याज दरों पर पड़ता है और घरों तथा व्यवसायों के लिए कर्ज लेना महँगा हो सकता है। यही प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में मांग को नियंत्रित करने और मांग-जनित महँगाई को कम करने में मदद करती है। रेपो रेट बढ़ने का सबसे सीधा प्रभाव ऋण की लागत पर पड़ता है। यदि गृह ऋण, वाहन ऋण या व्यक्तिगत ऋण महँगे होते हैं, तो उपभोक्ता नए कर्ज लेने या बड़ी खरीदारी करने से बच सकते हैं। मौजूदा ऋण लेने वालों की ईएमआई भी बढ़ सकती है, जिससे उनकी मासिक आय का बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में चला जाता है। परिणामस्वरूप उनके पास गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने के लिए कम धन बचता है। उपभोग में यह कमी कुल मांग को नियंत्रित करती है और मांग के अत्यधिक दबाव से पैदा होने वाली महँगाई को कम करने में मदद करती है।

इसका प्रभाव केवल परिवारों तक सीमित नहीं रहता। कंपनियाँ भी बैंक ऋण के माध्यम से नए कारखाने, मशीनरी, भवन और कारोबारी परियोजनाएँ शुरू करती हैं। ब्याज दर बढ़ने पर परियोजनाओं की वित्तीय लागत बढ़ जाती है। कई कंपनियाँ ऐसे निवेश को कुछ समय के लिए टाल सकती हैं, जिनसे अपेक्षित लाभ ब्याज लागत की तुलना में कम हो। इससे अत्यधिक आर्थिक गतिविधि पर कुछ नियंत्रण आता है और अर्थव्यवस्था में मांग का दबाव कम हो सकता है। रेपो रेट का एक महत्वपूर्ण प्रभाव बैंकिंग प्रणाली में ऋण वृद्धि पर भी पड़ता है। महँगे ऋण के कारण बैंक ऋण की मांग घट सकती है। यदि अर्थव्यवस्था में कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा हो और उसके कारण उपभोग तथा निवेश असामान्य रूप से बढ़ रहे हों, तो मौद्रिक सख्ती उस गति को संतुलित करने का काम करती है। महँगाई केवल वर्तमान कीमतों का विषय नहीं है; भविष्य में कीमतें कितनी बढ़ेंगी, इसकी लोगों की धारणा भी महत्वपूर्ण होती है। जब आरबीआई महँगाई के दबाव के बीच रेपो रेट बढ़ाता है, तो वह बाजार को यह संकेत देता है कि केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। इससे महँगाई की अपेक्षाओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यदि व्यवसायों और उपभोक्ताओं को विश्वास हो कि केंद्रीय बैंक कीमतों को अनियंत्रित नहीं होने देगा, तो वे भविष्य की कीमतों और मजदूरी को लेकर अत्यधिक मुद्रास्फीतिकारी निर्णय लेने से बच सकते हैं।

रेपो रेट में बढ़ोतरी का एक अन्य संभावित प्रभाव रुपये की विनिमय दर पर पड़ सकता है। अपेक्षाकृत ऊँची घरेलू ब्याज दरें वित्तीय परिसंपत्तियों को अधिक आकर्षक बना सकती हैं और पूँजी प्रवाह को समर्थन मिल सकता है। इससे रुपये पर अत्यधिक अवमूल्यन का दबाव कम हो सकता है। भारत कच्चे तेल सहित कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करता है। रुपये की कमजोरी से आयात महँगा होता है और इससे आयातित महँगाई बढ़ सकती है। इसलिए विनिमय दर में स्थिरता भी महँगाई नियंत्रण में अप्रत्यक्ष भूमिका निभा सकती है।

उपचुनावों में करारी शिकस्त के बाद अब किस पर ठीकरा फोड़ेगी कांग्रेस?

अशोक भाटिया



भारतीय लोकतंत्र का मिजाज अब पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का चुनावी शिकस्त के बाद का बर्ताव आज भी पुराना और पूरी तरह अनुमानित नजर आता है। हाल ही में अक्टूबर 2026 में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने एक बार फिर कांग्रेस की सांगठनिक कमजोरियों और वैचारिक खोखलेपन को पूरी तरह उजागर कर दिया है। असम की प्रतिष्ठित नगांव लोकसभा सीट से लेकर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और मुस्लिम-बहुल रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र, तथा पुदुचेरी की थट्टांचवडी सीट तक–हर तरफ कांग्रेस को करारी और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। इस ताजा चुनावी झटके ने राजनीतिक गलियारों में एक गंभीर और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि लगातार मिल रही इन पराजयों के बाद अब कांग्रेस अपनी नाकामी का ठीकरा किस संवैधानिक संस्था, व्यक्ति या व्यवस्था के सिर पर फोड़ेगी?

कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व का यह इतिहास रहा है कि जब भी चुनावी नतीजे उनके विपरीत आते हैं, वे बिना किसी पुख्ता सबूत के देश की सबसे विश्वसनीय संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। इन उपचुनावों के मतदान से ऐन पहले, दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया उग्र प्रदर्शन इसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था। कांग्रेस ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आड़ में करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे जाने और वोट चोरी का एक भ्रामक नैरेटिव गढ़ने की पुरजोर कोशिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के वैधानिक स्पष्टीकरणों और स्वतंत्र जांचों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का इस पर बेहद कड़ा और तार्किक पक्ष है कि जब कांग्रेस हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना में चुनाव जीतती है, तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निर्वाचन प्रणाली बिल्कुल पवित्र हो जाती है, लेकिन असम के नगांव या बंगाल के रेजीनगर में जनता जब उन्हें नकार देती है, तो वही व्यवस्था कठपुतली नजर आने लगती है। यह दोहरा रवैया न केवल देश के करोड़ों मतदाताओं के विवेक का अपमान है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने का एक गैर-जिम्मेदाराना प्रयास भी है। पश्चिम बंगाल की रेजीनगर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे कांग्रेस के पारंपरिक तुष्टिकरण के नैरेटिव पर सबसे बड़ा और सीधा प्रहार हैं। लगभग 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार शंखराव सरकार ने करीब 75,000 से अधिक वोटों के विशाल अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस सीट पर कांग्रेस दूर-दूर तक मुकाबले में भी नजर नहीं आई।

कांग्रेस हमेशा से यह मानकर चलती रही है कि देश का अल्पसंख्यक मतदाता उसका बंधुआ वोट बैंक है, जिसे केवल बहुसंख्यक राष्ट्रवाद का डर दिखाकर हर बार हासिल किया जा सकता है। लेकिन रेजीनगर की समझदार जनता ने यह साबित कर दिया है कि अब देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, केवल मुफ्त के खोखले वादों या डराने की राजनीति के बहकावे में आने वाला नहीं है। जनता अब सड़कों के निर्माण, आधुनिक अस्पतालों, बेहतर शिक्षा और औद्योगिक पार्कों जैसे बुनियादी विकास को प्राथमिकता दे रही है। कांग्रेस अपनी इस वैचारिक और रणनीतिक हार को स्वीकार करने के बजाय, इस जनादेश को भी ह्यध्रुवीकरण का दुष्परिणामह्व बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, जो यह दशार्ता है कि पार्टी अभी भी जमीनी हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

जब चुनाव आयोग और ईवीएम पर उठाए गए सवाल जनता के बीच बेअसर साबित होने लगते हैं, तो कांग्रेस अपने तरकश से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का पुराना तीर निकाल लेती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का यह लगातार आरोप रहता है कि भाजपा सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय का भय दिखाकर विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करती है और स्वतंत्र रूप से प्रचार नहीं करने देती। लेकिन सच यह है कि ये तमाम जांच एजेंसियां माननीय अदालतों और न्यायपालिका के कड़े निदेर्शों तथा प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर ही कानूनी कार्रवाई करती हैं। चुनाव में पराजय मिलने पर इसे जनता का साफ फैसला मानने के बजाय सत्तारूढ़ दल द्वारा लोकतंत्र के दमन का परिणाम घोषित कर देना कांग्रेस की आदत बन चुकी है।

भाजपा और राजनीतिक विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस लगातार विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी आंतरिक कमजोरियों, नेतृत्वहीनता और दिशाहीन नीति को छिपाने का प्रयास करती है, लेकिन देश की जागरूक जनता अब इस राजनीतिक ड्रामे के पीछे की असलियत को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है।

इन उपचुनावों के नतीजों ने न केवल कांग्रेस की सांगठनिक अक्षमता को उजागर किया है, बल्कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर की गहरी दरारों को भी सरेआम कर दिया है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा कांग्रेस की रणनीतियों पर सरेआम सवाल उठाना और राहुल गांधी के आंदोलन से खुद को दूर रखना यह साफ करता है कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस के बोझ को ढोने के मूड में नहीं हैं। पुदुचेरी की थट्टांचवडी सीट पर कांग्रेस की करारी हार ने यह साबित कर दिया है कि दक्षिण भारत में भी उसकी पकड़ लगातार ढीली हो रही है। क्षेत्रीय दलों को अब यह भली-भांति समझ आ गया है कि कांग्रेस के पास न तो कोई स्पष्ट राष्ट्रीय विजन है और ना ही भाजपा के मजबूत विकासवादी नैरेटिव का कोई व्यावहारिक तोड़। शीर्ष स्तर पर खुद को विपक्ष का इकलौता चेहरा साबित करने की राहुल गांधी की होड़ ने गठबंधन के अन्य मजबूत सहयोगियों के भीतर एक गंभीर असुरक्षा और असंतोष की भावना पैदा कर दी है, जिसका सीधा चुनावी नुकसान जमीन पर देखने को मिल रहा है। जब बाहरी बहानों की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तो कांग्रेस का आंतरिक तंत्र एक विशेष रक्षात्मक मुद्रा अपना लेता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य गांधी परिवार के शीर्ष नेतृत्व को किसी भी प्रकार की जवाबदेही से सुरक्षित बचाना होता है। इन उपचुनावों में भी, असम के नगांव में सिबामनी बोरा की करारी हार और बंगाल के नंदीग्राम में मिली शिकस्त के बाद, प्रदेश स्तर के नेताओं की आपसी गुटबाजी, स्थानीय स्तर पर कमजोर प्रबंधन और भीतरघात को मुख्य कारण ठहराया जाने लगा है। प्रादेशिक अध्यक्षों और स्थानीय प्रभारियों पर हार का सारा ठीकरा फोड़कर शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह पाक-साफ घोषित कर दिया जाता है। इस सामंती और दरबारी संस्कृति के कारण पार्टी के भीतर कभी भी ईमानदार और पारदर्शी आत्ममंथन नहीं हो पाता। जब तक पार्टी हार के वास्तविक कारणों–जैसे कार्यकताओं की उपेक्षा, राष्ट्रीय विजन का अभाव और जमीनी मुद्दों से दूरी–पर खुलकर चर्चा नहीं करेगी, तब तक सुधारात्मक कदम उठा पाना पूरी तरह असंभव है। अक्टूबर 2026 के ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए महज एक चुनावी हार नहीं हैं, बल्कि एक गंभीर और निर्णायक चेतावनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा- एनडीए का विकसित भारत का संकल्प, बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत नीतियां देश के मतदाताओं के दिलों में गहरा विश्वास पैदा कर चुकी हैं। जनता अब खोखली बयानबाजी, संसद से सड़क तक के ड्रामे और संवैधानिक संस्थाओं पर किए जाने वाले निराधार हमलों से पूरी तरह ऊब चुकी है। कांग्रेस को अब यह समझना ही होगा कि चुनाव सोशल मीडिया के नैरेटिव या विदेशी दौरों पर दिए गए बयानों से नहीं, बल्कि देश के आम नागरिकों के सुख-दुख में उनके साथ खड़े होने और जमीनी स्तर पर कड़ा संघर्ष करने से जीते जाते हैं। अगर कांग्रेस अब भी अपनी हर वैधानिक हार का ठीकरा चुनाव आयोग, ईवीएम, केंद्रीय एजेंसियों या परिस्थितियों पर फोड़ती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय राजनीति के मुख्य पटल से उसका अस्तित्व पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगा। समय की मांग है कि कांग्रेस बहानों की राजनीति को छोड़कर एक जिम्मेदार और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना सीखे।

दिल्ली में लोकतंत्र बनाम सुरक्षा का महासंग्राम!

वैश्विक स्तरपर 9 अक्टूबर 2026 मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन ने राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक बहस तेज कर दी है।प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने, दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों पर पार्बंदियों की तैयारी और दिल्ली पहुंचने वाली कुछ मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने के फैसलों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं?।क्या यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने की एहतियाती रणनीति है या इसका असर नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर भी पड़ रहा है? यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। मीडिया के हवाले से बताना चाहूंगा कि यहाँ 57 मेट्रो स्टेशन और रेल सेवाओं पर पाबंदी से बढ़ा विवाद, रेलवे बोर्ड के 9 अक्टूबर के आदेशके अनुसार निर्धारित समयावधि में नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके शुरूआती स्टेशनों से रद्द किया गया है। ये पाबंदियां 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पहुंचने वाली संबंधित ट्रेनों पर लागू बताई गई हैं। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने की व्यवस्था की घोषणा की है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पार्बंदियों का प्रभाव रेड, येलो, ब्लू, वायलेट,पिंक और मैजेंटा लाइनों सहित कई मेट्रो मार्गों पर पड़ना है। इससे यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और दूसरे जरूरी कामों से दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो सकतीहै।हालांकि सभी ट्रेनों के रद्द होने या पूरी मेट्रो सेवा बंद होने का दावा करना सही नहीं होगा पार्बंदियों का वास्तविक दायरा संबंधित आधिकारिक आदेशों से ही स्पष्ट होगा।

साथियों बात अगर हम सीजेपी का ऐलान युवाओं से डरती है सरकार तो पूरा देश बंद कर दे को समझने की करें तो, सीजेपी के संस्थापक ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि जंतर-मंतर निर्धारित प्रदर्शन स्थल है और पार्टी हर हाल में प्रदर्शन करेगी। उनका तर्क है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है और कथित चुनावी अनियमितताओं पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया है, जबकि जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। पार्टी ने देशभर में अपने कम से कम 10 हजार सदस्यों को हिरासत में लिए जाने का दावा भी किया है, लेकिन इस संख्या की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस दावे को स्थापित तथ्य के बजाय पार्टी के आरोप के रूप में ही सटीकता से देखा जाना चाहिए।

साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट में उठा सवाल सुरक्षा या नागरिक अधिकार? इसको समझने की करें तोअब इस विवाद ने न्यायिक स्तर पर भी ध्यान खींचा है।वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रदर्शन से पहले रेल सेवाओं, मेट्रो स्टेशनों तथा इंटरनेट सेवाओं पर संभावित पार्बंदियों को लेकर चिंता जताई।सिब्बल ने सवाल उठाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए राजधानी आने वाले लोगों की आवाजाही पर इतनी व्यापक रोक क्यों लगाई जा रही है। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस को खुली छूट देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने युवाओं के भविष्य और उनके परिवारों पर कानूनी कार्रवाई के प्रभाव को ध्यान में रखने की बात कही। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि आदतन अपराधियों या गंभीर अपराधों के आरोपियों को पूर्व आदेशों के तहत मिली सुरक्षा का लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। न्यायालय की इस टिप्पणी का अर्थ कानून-व्यवस्था की आवश्यकता को नकारना नहीं,बल्कि कार्रवाई में सटीकता से उचित संतुलन बनाए रखना है। साथियों बात अगर हम अघोषित आपातकाल का आरोप और 1942 के आंदोलन से तुलना को समझने की करें तो, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीडियो संदेश में गिरफ्तारियों,दिल्ली आने से रोके जाने और परिवहन प्रतिबंधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इन परिस्थितियों की तुलना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से करते हुए इसे अघोषित आपातकाल करार दिया। यह उनका राजनीतिक आरोप है, कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं। उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखने की अपील की है। दूसरी ओर, प्रशासन के सामने संभावित भीड़, यातायात, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे में दोनों पक्षों की कार्रवाइयों और दावों का आकलन प्रमाणों के आधार पर होना जरूरी है। साथियों बात अगर इस पूरे घटनाक्रम का महत्व किसी एक पार्टी या एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है इसको समझने की करें तो, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो उनका पारदर्शी और तथ्याधारित जवाब देना संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। उसी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा करना भी लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। प्रशासन को सुरक्षा संबंधी कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन उनकी आवश्यकता, अनुपात और नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा भी जरूरी है। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों को कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि 10 अक्टूबर का घटनाक्रम इस बात की कसौटी बनेगा कि लोकतंत्र में असहमति को किस तरह संभाला जाता है। न तो बिना प्रमाण सरकार के डरने का निष्कर्ष निकालना उचित है और न ही सुरक्षा के नाम पर हर प्रतिबंध को स्वतः न्यायसंगत मानना।

नोबेल शांति पुरस्कार 2026: ट्रंप की उम्मीदों पर फिरा पानी! भारतीय मूल की नावी पिल्लई ने मारी बाजी

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी



वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे प्रतिष्ठित शांति सम्मानों में शामिल नोबेल शांति पुरस्कार 2026 की घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान मिलने की अटकलों के बीच नॉर्वे की नोबेल समिति ने भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद् नावी पिल्लई को विजेता घोषित किया। यह फैसला केवल एक प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा नहीं, बल्कि मानवाधिकारों, अंतरराष्ट्रीय कानून और युद्ध अपराधों के विरुद्ध न्याय की महत्ता को रेखांकित करने वाला घटनाक्रम है। ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में युद्धविराम कराने और शांति स्थापित करने में भूमिका निभाई है। ऐसे माहौल में उनका नाम चर्चा में रहने के बावजूद पुरस्कार किसी राजनेता के बजाय दशकों से मानवाधिकारों और न्याय के लिए काम करने वाली महिला को मिलना सटीकता से वैश्विक सुर्खियों का विषय बन गया है।

साथियों बात अगर हम नावी पिल्लई कौन हैं और उन्हें क्यों मिला यह सम्मान? इसको समझने की करें तो नावी पिल्लई का पूरा नाम नवनेथम पिल्लई है। उनका जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारतीय तमिल मूल के परिवार में हुआ था। रंगभेद के दौर में सामाजिक भेदभाव के अनुभवों ने उनके जीवन और कानूनी संघर्ष को गहराई से प्रभावित किया।

वर्ष 1967 में वह नटाल क्षेत्र में वकालत शुरू करने वाली पहली महिला बनीं और दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश भी बनीं। उनका योगदान दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जुड़ीं और वर्ष 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त रहीं। उन्होंने युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों, नरसंहार और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार काम किया।नोबेल समिति ने 9 अक्टूबर 2026 को उन्हें शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए सम्मानित करने की घोषणा की। समिति के अनुसार, पिल्लई ने शक्तिशाली देशों और राष्ट्रीय नेताओं को भी जवाबदेह ठहराने तथा हिंसा और संघर्ष के पीड़ितों में न्याय की उम्मीद जगाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

साथियों बात अगर हम नोबेल समिति के अध्यक्ष ने क्या कहा? इसको समझने की करें तो, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष योर्गेन वाटने फ्राइडनेस ने घोषणा करते हुए कहा कि पिल्लई का काम अधिक शांतिपूर्ण दुनिया चाहने वाले लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत है। समिति की विज्ञप्ति में कहा गया कि जब युद्ध और संघर्ष बढ़ रहे हों तथा अंतरराष्ट्रीय कानून की संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव पड़ रहा हो, तब यह याद दिलाना आवश्यक है कि बल प्रयोग के बजाय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन पर निर्भर करता है। समिति ने यह भी रेखांकित किया कि ऐसा अंतरराष्ट्रीय कानूनी तंत्र, जिसमें युद्ध अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए और दुर्व्यवहार के पीड़ितों को न्याय मिले, शांतिपूर्ण दुनिया की बुनियादी शर्त है। इस वर्ष के पुरस्कार के लिए कुल 287 उम्मीदवार नामांकित थे, जिनमें एक चौथाई से कुछ अधिक संगठन थे।

साथियों बात अगर हम ट्रंप पर क्या प्रभाव पड़ा और मीडिया में कैसी प्रतिक्रिया है?

इसको समझने की करें तो अब डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिला,जबकि उनके शांति प्रयासों और विभिन्न संघर्षों में युद्धविराम कराने के दावों के कारण उनके समर्थकों के बीच इस संभावना की चर्चा थी। इसलिए घोषणा के बाद उनके समर्थकों की अपेक्षाओं और पुरस्कार की चयन प्रक्रिया को लेकर बहस होना स्वाभाविक है। हालांकि, यह कहना कि नोबेल समिति ने ट्रंप को निशाना बनाने के लिए पिल्लई को चुना, उपलब्ध तथ्यों से पुष्ट नहीं होता। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ओस्लो स्थित पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक हाकोन गेर्लोव ने भी इस चयन को ट्रंप पर सीधा हमला मानने से इनकार किया और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून-आधारित व्यवस्था को प्रोत्साहन देने वाला कदम बताया।

साथियों, अंतरराष्ट्रीय समाचार माध्यमों ने पिल्लई की न्यायिक पृष्ठभूमि, मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया है। उनकी अध्यक्षता वाले संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने गाजा के संबंध में नरसंहार का निष्कर्ष दिया था, जिसे इजरायल ने खारिज किया था। इस पृष्ठभूमि के कारण पुरस्कार की घोषणा को अंतरराष्ट्रीय न्याय, इजरायल-फलस्तीन विवाद और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं की भूमिका के व्यापक संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पुरस्कार से बड़ा संदेश, नावी पिल्लई को मिला नोबेल शांति पुरस्कार यह संदेश देता है कि शांति का अर्थ केवल युद्धविराम कराना नहीं, बल्कि न्याय, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा करना भी है। ट्रंप को पुरस्कार न मिलना राजनीतिक चर्चा का विषय अवश्य है, लेकिन इस निर्णय का वास्तविक महत्व किसी नेता की जीत या हार से आगे है। यह उस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि स्थायी शांति के लिए ताकत के साथ-साथ जवाबदेही, निष्पक्ष न्याय और मानवीय गरिमा का सम्मान भी अनिवार्य है।

वन्यजीवों की घटती आबादी, जैव विविधता संकट और संरक्षण की चुनौती

डॉ. प्रियंका सौरभ

पृथ्वी पर जीवन की विविधता मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। वन, नदियाँ, महासागर, घास के मैदान और आर्द्रभूमियाँ न केवल वन्यजीवों को आश्रय प्रदान करती हैं, बल्कि भोजन, स्वच्छ जल, जलवायु संतुलन तथा आजीविका के लिए भी आवश्यक हैं। किंतु तीव्र आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन और पर्यावरणीय असंतुलन ने जैव विविधता पर गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वन्यजीव आबादी में गिरावट के माध्यम से इसी संकट को उजागर करती है। यह केवल कुछ प्रजातियों के कम होने की कहानी नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच बिगड़ते संबंधों का प्रतिबिंब है।

रिपोर्ट में दर्ज वन्यजीव आबादी में गिरावट का अर्थ पृथ्वी पर मौजूद सभी पशुओं की कुल संख्या में समान अनुपात में कमी आना नहीं है। यह मुख्यतः निगरानी की गई स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर और मछली प्रजातियों की आबादी में समय के साथ हुए औसत परिवर्तन को दशार्ती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में बाघों, पक्षियों और मछलियों की आबादी लगातार घट रही है, तो यह उनके प्राकृतिक आवास, भोजन की उपलब्धता और प्रजनन परिस्थितियों में प्रतिकूल बदलाव का संकेत हो सकता है। इसी प्रकार, मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में आबादी की तीव्र गिरावट नदियों, झीलों और आर्द्रभूमियों पर बढ़ते दबाव को दशार्ती है। हालाँकि, आबादी में गिरावट और प्रजातियों के विलुप्त होने के बीच अंतर है। कुछ प्रजातियों की संख्या घटने का अर्थ यह नहीं कि वे विलुप्त हो चुकी हैं। इसलिए वन्यजीवों की घटती आबादी को प्रकृति के स्वास्थ्य का चेतावनी संकेतक समझना चाहिए, न कि सभी जीवों के कुल विनाश का प्रत्यक्ष माप।

जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश और विखंडन है। वनों की कटाई, कृषि भूमि का विस्तार, खनन, शहरीकरण, सड़क निर्माण तथा औद्योगिक परियोजनाएँ वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को सीमित कर देती हैं। जब जंगल छोटे-छोटे हिस्सों में बँट जाते हैं, तो जानवरों की आवाजाही, प्रजनन और भोजन प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित होती है। भारत में वन क्षेत्रों के निकट मानव बस्तियों और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हाथियों तथा तेंदुओं के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष को बढ़ा सकता है। प्राकृतिक आवासों का विनाश केवल जीवों को आश्रय से वंचित नहीं करता, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य शृंखला और प्राकृतिक संतुलन को भी कमजोर करता है। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन भी जैव विविधता के लिए गंभीर चुनौती है।

छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : रेखा गुप्ता

योगेश कुमार



नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में अंधेरी जगहें, लाइटिंग की कमी, टूटे फूटपाथ और कचरे की समस्या के जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार देर रात दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस पहुंचीं। यहां उन्होंने आर्ट्स फैकल्टी के बाहर छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी सुरक्षा, परिवहन, हॉस्टल और कॉलेज से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से बातचीत करते हुए पूछा कि रात में आने-जाने में कोई परेशानी या असुरक्षा तो महसूस नहीं होती और कॉलेज से जुड़ी कोई समस्या हो तो वह भी उन्हें बताएं। उन्होंने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि उनकी हर उचित समस्या के समाधान के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कैंपस में निरीक्षण करते हुए कई डार्क स्पॉट देखे और अधिकारियों से मौके पर ही उनकी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़क पर पर्याप्त रोशनी होने के बावजूद कैंपस के अंदर कई स्थानों पर अंधेरा दिखाई दे रहा है, जबकि यहां छात्राओं और विद्यार्थियों की लगातार आवाजाही रहती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर वहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पेड़ों की अनावश्यक शाखाओं की छंटाई कराने और जहां जरूरत हो, वहां अतिरिक्त लाइट लगाने के निर्देश भी दिए गए ताकि पेड़ों की वजह से रोशनी बाधित न हो। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर टूटे और असमान फुटपाथ देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फुटपाथ ऐसी स्थिति में नहीं होने चाहिए कि विद्यार्थियों को चलने में परेशानी हो। उन्होंने विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखने को कहा और निर्देश दिया कि पूरे मार्ग की जांच कर जहां भी फुटपाथ क्षतिग्रस्त या असमान हैं, उन्हें तत्काल ठीक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कैंपस में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि कितने कैमरे लगे हैं, उनमें से कितने काम कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त कैमरों की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां सीसीटीवी की आवश्यकता है, वहां जल्द कैमरे लगाए जाएं और पहले से लगे कैमरों की कार्यशीलता की भी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि कैंपस का कोई भी संवेदनशील क्षेत्र निगरानी से बाहर नहीं रहना चाहिए। छात्राओं से कैंपस में पीसीआर की मौजूदगी और रात के समय महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के बारे में भी पूछा। रात में महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहती हैं और आवश्यकता पड़ने पर पीसीआर भी तुरंत पहुंचती है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस तथा विश्वविद्यालय प्रशासन को आपसी समन्वय से काम करने पर जोर दिया। कैंपस में जगह-जगह गंदगी और खराब ग्रीन बेल्ट देखकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सवाल किया और तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय ऐसा स्थान है जहां हर दिन हजारों विद्यार्थी आते-जाते हैं। इसलिए यहां साफ-सफाई, रोशनी, सुरक्षित रास्ते और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित करना जरूरी है। पीजी से जुड़ी समस्याओं पर भी मुख्यमंत्री ने छात्राओं से विस्तार से बातचीत की। छात्राओं द्वारा पीजी की स्थिति और सुविधाओं से जुड़ी परेशानी बताए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द पीजी पॉलिसी लेकर आ रही है, जिससे पीजी व्यवस्था में आवश्यक नियम और मानक तय किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए नए हॉस्टलों के निर्माण और बेहतर हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है, ताकि विद्यार्थियों को रहने के लिए सुरक्षित और बेहतर विकल्प मिल सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आर्ट्स फैकल्टी, लॉ फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, पार्किंग और अन्य संवेदनशील हिस्सों का दोबारा निरीक्षण कर कम रोशनी वाले स्थानों पर आवश्यक सुधार किए जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। निरीक्षण में सामने आई प्रत्येक समस्या का समाधान बिना किसी देरी के किया जाए और दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की बाद में समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को लेकर भी बातचीत की और कहा कि छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए और इसके लिए वे थोड़ा समय निकालें।

मुख्यमंत्री ने 'प्लांट मंडला रंगोली' का किया उद्घाटन



छाया : ओमप्रकाश

ओमप्रकाश

नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क के एम्फीथिएटर में प्लांट मंडला रंगोली का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्लांट मंडला का अवलोकन किया और उपस्थित लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मंडला रंगोली भारतीय कला और संस्कृति की सुंदर एवं समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। इस विशेष कार्यक्रम में कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, विधायक अशोक गोयल उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंडला में लगाया गया प्रत्येक पौधा केवल कलात्मक रचना का हिस्सा नहीं, बल्कि पौधे लगाने, उनकी रक्षा और पोषण करने तथा दिल्ली के वन एवं शहरी हरित क्षेत्रों को संरक्षित और विकसित करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जिस प्रकार मंडला के प्रत्येक तत्व से मिलकर एक सुंदर रचना पूर्ण होती है, उसी प्रकार प्रत्येक पौधा और हरित क्षेत्र मिलकर स्वस्थ पर्यावरण और बेहतर जीवन-स्तर के निर्माण में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि इस 'प्लांट मंडला रंगोली' के माध्यम से 'विकसित भारत 2047' और 'विकसित दिल्ली'के संकल्प को भी एक साथ अभिव्यक्त किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों के सामने रखे गए 'हम करके रहेंगे' के संकल्प और विश्वास को आज इस अनूठी पौधों की रंगोली के माध्यम से दोहराया गया है। यह संदेश केवल आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर आगे बढ़ने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शादीपुर फ्लाईओवर के नीचे 24 ग्राम संदिग्ध एमडीएमए के साथ घाना का नागरिक गिरफ्तार



नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। सेंट्रल जिले के पटेल नगर थाना पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 वर्षीय घाना निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 24 ग्राम क्रिस्टलनुमा सफेद पदार्थ बरामद किया है, जिसके एमडीएमए/मेथामफेटामाइन होने का संदेह है। आरोपी की पहचान कूमसन फ्रांसिस अतुआ, उम्र 30 वर्ष, निवासी चंद्र विहार, दिल्ली, मूल निवासी घाना के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, 6 अक्टूबर को पटेल नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक अफ्रीकी नागरिक शादीपुर फ्लाईओवर, बलजीत नगर के नीचे किसी व्यक्ति को एमडीएमए और कोकीन जैसी नशीली पदार्थों की खेप सप्लाई करने आने वाला है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसीपी पटेल नगर को अवगत कराया गया और एसएचओ पटेल नगर की निगरानी तथा एसीपी पटेल नगर के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम गठित की गई।

पुलिस टीम गुप्त सूचना के आधार पर शादीपुर फ्लाईओवर पहुंची। मौके पर गुप्त सूचना देने वाले ने एक अफ्रीकी नागरिक की पहचान संदिग्ध के रूप में की, जिसके बाद पुलिस ने उसे तत्काल दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके ट्राउजर की दाहिनी जेब से पॉलीथिन में रखा क्रिस्टलनुमा सफेद पदार्थ बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने इसे एमडी बताया। इसके बाद क्राइम टीम/एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बरामद पदार्थ को जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर संख्या 337/2026, धारा 22(बी) एनडीपीएस अधिनियम, थाना पटेल नगर, सेंट्रल जिला के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया।

मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त



नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को गंभीर अपराधों में मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के मामलों पर कड़ी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि अपराधियों को 'माफ' करने की एक सीमा होनी चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हर बार नरमी दिखाने और माफ करने की प्रवृत्ति पर कहीं न कहीं तो रोक लगनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हमारे पास माफ करने के रवैये और 'सबसे दुर्लभ मामलों' (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) के सिद्धांत का बार-बार लाभ दिए जाने के कारण देश में अपराध की स्थिति पर असर पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि एक समय हत्या के मामलों में 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' सिद्धांत इसलिए लागू होता था, क्योंकि उस समय हत्या के अपराध भी अपेक्षाकृत दुर्लभ थे लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। एक पुराने केस का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि एक पिता ने अपनी बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और बाद में हत्या कर दी। मां की गवाही पर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में वह पैरोल पर बाहर निकला और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। न्यायालय ने कहा कि इस बार गवाह उसकी छोटी बेटी थी, जिसके आधार पर उसे मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि, बाद में उच्चतम न्यायालय ने उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

युवा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाएं : विजेंद्र गुप्ता

जितेन्द्र राणा



नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि युवाओं को कभी भी अपने जोश पर होश हावी नहीं होने देना चाहिए। आपकी ऊर्जा, विचार और आकांक्षाएं तभी सार्थक हैं, जब उन्हें जागरूकता, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना का मार्गदर्शन मिले। यह बात विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा का भ्रमण करने आए विद्यार्थियों के संवाद के दौरान कही। महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल नवर्चना विद्याणी विद्यालय (वडोदरा) तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और रामजस कॉलेज के विद्यार्थियों ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण किया। यह भ्रमण युवाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़ने तथा उन्हें भारत की संसदीय परंपराओं, संवैधानिक मूल्यों और विधायी प्रक्रियाओं से परिचित कराने की विधानसभा की निरंतर पहल का हिस्सा था। इस संवाद ने विभिन्न क्षेत्रों और शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से आए छात्रों को विधानसभा अध्यक्ष के साथ सीधे संवाद करने तथा कक्षा और पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर विधायिका के कामकाज को समझने का अवसर प्रदान किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि युवाओं में अपार ऊर्जा, जिज्ञासा और आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन इनका साथ जागरूकता, धैर्य और विवेक से होना आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहने, सोच-समझकर निर्णय लेने और अपनी क्षमताओं का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने आसपास हो रहे बदलावों का केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनमें ऐसी समझ और जिम्मेदारी की भावना विकसित होनी चाहिए।

द्वारका में प्रतिबंधित ई-सिगरेट के अवैध कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, 106 ई-सिगरेट बरामद



नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। युवाओं और स्कूली छात्रों के बीच प्रतिबंधित ई-सिगरेट की बिक्री एवं आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए द्वारका जिला पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में स्पेशल स्टाफ, द्वारका की टीम ने सेक्टर-12 स्थित एक पान सेंटर पर छापेमारी कर प्रतिबंधित ई-सिगरेट की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 106 प्रतिबंधित ई-सिगरेट बरामद करते हुए दुकान संचालक 52 वर्षीय लालचंद, निवासी उत्तम नगर, दिल्ली को गिरफ्तार किया है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह, आईपीएस के निर्देश पर प्रतिबंधित ई-सिगरेट की बिक्री और आपूर्ति करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का विशेष उद्देश्य उन स्थानों पर नजर रखना है, जहां युवा और छात्र अधिक संख्या में आते-जाते हैं। पुलिस ने प्रतिबंधित ई-सिगरेट के अवैध कारोबार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पुलिस के अनुसार, डीसीपी द्वारका के निर्देश पर एसीपी ऑपरेशंस द्वारका सुभाष मलिक की निगरानी में स्पेशल स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में एसआई दिनेश कुमार, एसआई टोपीश, एएसआई विजय सिंह, हेड कांस्टेबल नरेश, हेड कांस्टेबल राजेश और हेड कांस्टेबल जयराम को शामिल किया गया। टीम को प्रतिबंधित ई-सिगरेट की बिक्री और आपूर्ति में शामिल लोगों की पहचान कर उनके ठिकानों का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

जांच के दौरान पुलिस टीम ने स्थानीय स्तर पर मुखबिरों को सक्रिय किया और प्रतिबंधित ई-सिगरेट की बिक्री करने वाले दुकानदारों तथा उनके ठिकानों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। इसी दौरान पुलिस को एक दुकान में प्रतिबंधित ई-सिगरेट की बिक्री किए जाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर 5 अक्टूबर 2026 को स्पेशल स्टाफ की टीम ने जी-4, सेक्टर-12, द्वारका में स्थित ह्लआर्यन पान सेंटरह्व पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दुकान संचालक लालचंद को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दुकान से अलग-अलग ब्रांड और फ्लेवर की कुल 106 प्रतिबंधित ई-सिगरेट बरामद हुईं। पुलिस के मुताबिक बरामद ई-सिगरेट में INOX PLASMA की 58, IGET SOUL B40000 की 33, OLIVE BAR की 10 और ELF BAR की 5 ई-सिगरेट शामिल हैं। पूछताछ के दौरान लालचंद बरामद प्रतिबंधित ई-सिगरेट रखने और उनके स्रोत के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

मायापुरी पुलिस ने सुलझाई सेंधमारी की वारदात, दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। पश्चिमी जिला पुलिस के मायापुरी थाना पुलिस ने सेंधमारी के एक मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने के आभूषण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय मोहम्मद साहिल उर्फ बाबू , निवासी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और 20 वर्षीय मोहम्मद आजाद, निवासी न्यू सीमापुरी, दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मोहम्मद साहिल पहले से आठ आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है।

पुलिस के मुताबिक 30 सितंबर 2026 को नांगल राया निवासी नीतू ने अपने घर में सेंधमारी और सोने के आभूषण चोरी होने की शिकायत मायापुरी थाने में दी थी। शिकायत के आधार पर ई-एफआईआर संख्या 80083154/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 305/331(3) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मायापुरी थाना पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम में एसआई मनीष कलकल, हेड कांस्टेबल महेश, हेड कांस्टेबल देवेंद्र, हेड कांस्टेबल देवेंद्र और हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह को शामिल किया गया। टीम ने थाना प्रभारी मायापुरी और एसीपी मायापुरी की निगरानी में तथा पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी के पर्यवेक्षण में जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला।

35 लाख की चोरी का खुलासा, नई नौकरानी निकली कथित मास्टरमाइंड

सोने-हीरे के आभूषण समेत सिंगापुर, मलेशिया और यूएई की विदेशी मुद्रा बरामद, 100 प्रतिशत चोरी का माल बरामद



नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र के राणा प्रताप बाग में हुई लाखों रुपये की हाई-वैल्यू चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला की पहचान 30 वर्षीय ज्योति पत्नी चंदर प्रकाश, निवासी बाबा कॉलोनी, बुराड़ी के रूप में हुई है, जो शिकायतकर्ता परिवार के यहां हाल ही में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने लगी थी। पुलिस का दावा है कि पूछताछ और जांच के दौरान ज्योति की कथित भूमिका इस वारदात की मास्टरमाइंड के रूप में सामने आई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही और जांच के दौरान चोरी की संपत्ति की 100 प्रतिशत बरामदगी का दावा किया है। बरामद सामान में करीब 35 लाख रुपये कीमत के सोने और हीरे के आभूषण, विदेशी मुद्रा, नकदी तथा अन्य सामान शामिल हैं। पुलिस के अनुसार 29 सितंबर 2026 को भारत नगर थाना क्षेत्र में हाई-वैल्यू चोरी की शिकायत मिलने के बाद ई-एफआईआर संख्या 80082781 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 305/331(4) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए संगम पार्क पुलिस चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक राजेश पिलानिया, हेड कांस्टेबल अजय और हेड कांस्टेबल सुनील की टीम गठित की गई। टीम ने थाना भारत नगर के एसएचओ इंस्पेक्टर राम किशोर के नेतृत्व और एसीपी अशोक विहार आकाश रावत की निगरानी में जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने मानवीय सूचना, तकनीकी निगरानी और मैदानी स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर संदिग्धों की गतिविधियों की पड़ताल की। इसी दौरान शिकायतकर्ता परिवार के यहां हाल ही में काम पर लगी घरेलू सहायिका ज्योति पर पुलिस का शक गहराया। जिसके बाद चोरी की संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया गया। चोरी का सामान आरपी बाग स्थित देसू कॉलोनी इलाके में छिपाए जाने की सूचना मिलने के बाद टीम ने वहां तलाश शुरू की। जांच के दौरान आरपी बाग क्षेत्र में घरेलू काम करने वाली विनिता से भी पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि विनिता से मिली महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर चोरी का माल बरामद किया गया। बरामद सामान में करीब 70 ग्राम की सोने की चेन, 40 ग्राम का सोने का कड़ा, सोने की सॉलिटेयर डायमंड अंगूठी, सोने की बालियों की एक जोड़ी, पेंडेंट सहित सोने की चेन, चांदी जैसी धातु की चेन, 313 सिंगापुर डॉलर, 250 मलेशियाई रिंगिट, 305 यूएई दिरहम और 4 हजार रुपये नकद शामिल हैं। इसके अलावा एक पेन ड्राइव, चोरी की लोहे की सेफ तथा कई लिफाफे और सिक्के भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी ज्योति का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।

जापानी पार्क के पास नकली नोटों का सिंडिकेट पकड़ा, चार गिरफ्तार



नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। रोहिणी जिला पुलिस की जिला जांच इकाई (डीआईयू) ने नकली भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई, आपूर्ति और वितरण से जुड़े एक कथित सिंडिकेट का पदार्फाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनसे जुड़े ठिकानों पर की गई तलाशी के दौरान करीब 10.50 लाख रुपये मूल्य के संदिग्ध नकली 500 रुपये के नोट, दो रंगीन प्रिंटर, पेपर कटिंग मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, नोट गिनने की मशीन और अन्य प्रिंटिंग सामग्री बरामद की है। पुलिस के अनुसार बरामद सामग्री का इस्तेमाल कथित तौर पर नकली नोट तैयार करने में किया जा रहा था। यह कार्रवाई डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल, के निर्देशन में एसीपी ऑपरेशन अजमेर सिंह की निगरानी और डीआईयू प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने की। टीम में एसआई आशीष, एएसआई अरविंद कुमार, हेड कांस्टेबल आशीष, अशोक व राहुल तथा कांस्टेबल अंकित शामिल रहे। पुलिस के अनुसार रोहिणी जिले में नकली भारतीय मुद्रा की बिक्री, परिवहन और वितरण पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमें लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। इसी क्रम में 30 सितंबर 2026 को डीआईयू टीम को सूचना मिली कि प्रशांत विहार थाना क्षेत्र में नकली भारतीय मुद्रा नोटों की आपूर्ति से जुड़े कुछ लोग सक्रिय हैं। आधार पर पुलिस टीम ने जापानी पार्क के पास कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों पुष्कर राज पुरबिया उर्फ 'डॉक्टर', गोसाई राम और साहिल खरब को पकड़ लिया। इनके पास से 500 रुपये मूल्य के संदिग्ध नकली नोट तथा नकली मुद्रा तैयार करने में कथित तौर पर इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद हुई। इस मामले में एफआईआर संख्या 282/2026, दिनांक 1 अक्टूबर 2026 को थाना प्रशांत विहार में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ, तकनीकी निगरानी और अन्य जांच के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं। जांच के दौरान पुलिस ने चौथे आरोपी नरेंद्र कुमार को राजस्थान के चूरू से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दो रंगीन प्रिंटर, पेपर कटिंग मशीन, दो एचपी लैपटॉप, नोट गिनने की मशीन, स्क्रीन प्रिंटिंग सामग्री, डेस्कटॉप कंप्यूटर व मॉनिटर, लेनोवो एलसीडी मॉनिटर, आईबॉल सीपीयू तथा बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग सामग्री बरामद की गई। पुलिस के अनुसार लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों में मौजूद डेटा की जांच की जा रही है। जांच के दौरान कुल 21 बंडलों में 500 रुपये मूल्य के संदिग्ध नकली नोट बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत करीब 10 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन नोटों की छपाई कहां की जाती थी, इनके लिए कच्चा माल कहां से लाया जाता था और इन्हें किन स्थानों पर खपाने की योजना थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पुष्कर राज पुरबिया उर्फ डॉक्टर (56) जयपुर, राजस्थान का रहने वाला है और प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करता था।

एक घंटे में झपटमारी का आरोपी गिरफ्तार, बैग-पर्स व नकदी बरामद

नई दिल्ली (सत्यम् लाइव)। मध्य जिला पुलिस ने झपटमारी की वारदात को महज एक घंटे में सुलझाते हुए एक शातिर झपटमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़ित का बैग, पर्स, पहचान पत्र, नकदी और कपड़े बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान 24 वर्षीय लव कुश, निवासी आजाद मार्केट, दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस की तत्पर कार्रवाई से न केवल तत्काल मामले का खुलासा हुआ, बल्कि पूछताछ के दौरान झपटमारी के एक अन्य मामले का भी पता चला। पुलिस के अनुसार, 6 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे शिकायतकर्ता मोरी गेट से पैदल अपने घर लौट रहा था। जब वह रानी झांसी रोड पर पहुंचा, तभी एक युवक उसके पास आया और उसका बैग झपटकर सड़क की दूसरी ओर फरार हो गया। बैग में पर्स, कपड़े, पहचान संबंधी दस्तावेज और नकदी रखी हुई थी। पीड़ित ने तत्काल पीसीआर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद थाना देशबंधु गुप्ता रोड में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पीसीआर कॉल मिलते ही पुलिस पोस्ट सिद्धीपुरा की टीम सक्रिय हो गई और शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए रास्ते की दिशा में तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने डीसीएम गोल चक्कर के पास स्थित एक पार्क में संदिग्ध हालत में छिपे एक युवक को दबोच लिया। पूछताछ में उसकी पहचान लव कुश के रूप में हुई।

तलाशी के दौरान उसके कब्जे से झपटा गया पिट्ठू बैग, पर्स, पहचान पत्र, नकदी और कपड़े बरामद हुए। शिकायतकर्ता ने मौके पर ही बरामद सामान की पहचान अपने सामान के रूप में की।

पुलिस टीम में एसआई विवेक सिंह, प्रभारी पुलिस चौकी सिद्धीपुरा, हेड कांस्टेबल महिपाल और कांस्टेबल शिशराम शामिल रहे।

किसान बोले, न आश्वासन से समझौता होगा, न अधिकारों से



नोएडा। भारतीय किसान यूनियन मंच के नेतृत्व में सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन पर 81 गांवों के किसानों का धरना अधिकारियों के आश्वासन के बाद 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी ने स्पष्ट किया कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। अगर इस अवधि में प्राधिकरण किसानों की मांगों पर ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता है, तो किसान अस्तित्व बचाओ आंदोलन फिर से उसी मजबूती से शुरू किया जाएगा। किसानों की आबादी, नक्शा नीति, पांच प्रतिशत प्लाट, वर्ष 1976-97 के किसान कोटे, गांवों के विकास और अन्य अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा।

प्राधिकरण को कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय दिया गया

त्यागी ने कहा कि प्राधिकरण को कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद आगे की रणनीति किसानों के साथ चर्चा कर तय की जाएगी। किसान अस्तित्व बचाओ आंदोलन के तहत बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में किसान फिर धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान विमल त्यागी ने प्रशासन और प्राधिकरण के साथ पिछले दिन हुई वार्ता की जानकारी दी। दोपहर करीब 3 बजे नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह और एसीपी प्रवीन कुमार सिंह किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने बैठक में हुई चर्चा और उसके विवरण से किसानों को अवगत कराया। अधिकारियों ने कहा कि प्राधिकरण किसानों की समस्याओं और वार्ता को लेकर गंभीर है तथा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। त्यागी ने बताया कि किसानों की आबादी और नक्शा नीति से जुड़े अहम विषय शासन स्तर पर रखे गए हैं। आगामी मंगलवार के आसपास लखनऊ में कैबिनेट स्तर की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें किसानों के इन मामलों पर चर्चा होगी।

पात्र किसानों के प्लॉट नहीं रोके जाने चाहिए

बैठक की जानकारी मिलने के बाद किसानों के साथ फिर वार्ता कर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। पांच प्रतिशत प्लाट के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। किसानों का कहना था कि केवल अतिक्रमण के नाम पर पात्र किसानों के प्लाट नहीं रोके जाने चाहिए। वर्ष 1976-97 के किसान कोटे के प्लाटों के संबंध में प्राधिकरण से जानकारी मांगी गई है कि कितने किसानों को आवंटन मिला और कितने अब भी अधिकार से वंचित हैं। गांवों के विकास का मुद्दा भी वार्ता में उठाया गया। संबंधित अधिकारियों को गांवों में जाकर विकास कार्यों का सर्वे करने और मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने को कहा गया। आंदोलन स्थल पर मौजूद किसानों और प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण को ठोस कार्रवाई के लिए 15 दिन देने पर सहमति जताई।

इंदिरापुरम की सोसायटी में आवारा कुत्तों का आतंक, महिला को काटकर किया घायल



साहिबाबाद। इंदिरापुरम स्थित शिप्रा रिवेरा सोसायटी में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक ने निवासियों के बीच भारी दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बुधवार सुबह हुई एक घटना के बाद से पूरी सोसायटी के लोग सहमे हुए हैं। यहां अपने घर के बाहर खड़ी एक महिला पर आवारा कुत्तों ने अचानक पीछे से हमला कर उन्हें बुरी तरह काट लिया।

घटना सुबह करीब 8 बजे की है। शिप्रा रिवेरा सोसायटी की निवासी प्रीति चौबे अपने घर के बाहर खड़ी थीं। इसी दौरान दो आवारा कुत्तों ने उन पर पीछे से अचानक हमला कर दिया। कुत्तों ने महिला को कई जगह काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोग उन्हें इलाज के लिए इंदिरापुरम स्थित अस्पताल ले गए। हालांकि, डॉक्टरों ने प्राथमिक स्थिति देखने के बाद इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद परिजन घायल महिला को इलाज के लिए नोएडा स्थित अस्पताल ले गए, जहां उनका उपचार कराया गया।

डिलीवरी बॉयज ने भी आने से किया इनकार

हमले के बाद से पूरी सोसायटी में डर का माहौल है। सुरक्षा को लेकर चिंतित निवासियों ने बताया कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि महिलाओं और बच्चों ने डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। केवल निवासी ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन सामान डिलीवर करने वाले डिलीवरी बॉयज भी सोसायटी के अंदर आने से मना करने लगे हैं।

70 से 80 लोग बन चुके हैं शिकार: एओए अध्यक्ष

सोसायटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशिर कानूनगो ने बताया कि सोसायटी में आवारा कुत्तों का आतंक कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व में भी लगभग 70 से 80 निवासियों को कुत्ते काट चुके हैं और वे घायल हुए हैं।

शिकायत के बाद नगर निगम की कार्रवाई

एओए अध्यक्ष और निवासियों का आरोप है कि नगर निगम में कई बार शिकायत करने के बावजूद पहले कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है। घटना और शिकायत के बाद नगर निगम की टीम हरकत में आई और कुत्तों को पकड़ने सोसायटी पहुंची। टीम ने महिला को काटने वाले कुत्ते समेत कुल दो कुत्तों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। निवासियों ने मांग की है कि सोसायटी को आवारा कुत्तों की समस्या से स्थायी रूप से निजात दिलाई जाए।

यीडा की 6210 करोड़ की हेरिटेज सिटी पर फिर पेच, बाढ़ के खतरे और लाइसेंस फीस पर मांगा जवाब



ग्रेटर नोएडा। मथुरा जिले में यीडा की हेरिटेज सिटी परियोजना को लेकर लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में दो बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित हेरिटेज सिटी के यमुना नदी की बाढ़ से प्रभावित होने की संभावना और लाइसेंस फीस पर सुझाव लेकर दोबारा प्रस्ताव सचिव समिति के सामने रखने को कहा गया है। यमुना प्राधिकरण के फेज दो में शामिल राया अर्बन सेंटर के तहत हेरिटेज सिटी परियोजना प्रस्तावित है। 750 एकड़ में प्रस्तावित इस परियोजना की लागत 6210 करोड़ रुपये अनुमानित है। परियोजना को एनएच 44 से यमुना एक्सप्रेसवे के बीच प्रस्तावित 15.3 किमी लंबी सड़क के दोनों ओर विकसित किया जाएगा। हेरिटेज सिटी परियोजना की निविदा को प्रदेश सरकार की निविदा मूल्यांकन समिति की स्वीकृति के बाद बुधवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित सचिव समिति की स्वीकृति के लिए रखा गया था, लेकिन समिति ने दो बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट कर बोर्ड के माध्यम से प्रस्ताव समिति के सम्मुख रखने के निर्देश दिए हैं। हेरिटेज सिटी की प्रस्तावित साइट यमुना नदी की बाढ़ से प्रभावित हो गई थी। सिंचाई विभाग से मूल्यांकन करा लिया जाए कि भविष्य में यमुना नदी में बाढ़ से हेरिटेज सिटी को किसी तरह का नुकसान हो नहीं होगा, इसके अलावा हेरिटेज सिटी के लिए लाइसेंस फीस तय की जाए या नहीं, इस पर भी राय लेकर यीडा को पहले बोर्ड व उसके बाद सचिव समिति के सम्मुख प्रस्ताव रखना होगा।

मुनाफा कमाने का झांसा देकर 72 वर्षीय बुजुर्ग से 27 लाख 50 हजार रुपए की ठगी

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोयडा में थाना साइबर क्राइम में एक 72 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने अपने जाल में फंसाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर उनसे 27 लाख 54 हजार रुपए की ठगी कर ली है। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम श्रीमती शैव्या गोयल ने बताया कि बीती रात को रजनीश त्यागी पुत्र राम नारायण सिंह त्यागी निवासी सेक्टर 29 ने थाना साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि साइबर अपराधियों ने उनसे संपर्क किया तथा कहा कि अगर वह शेयर मार्केट में इनवेस्ट करेंगे तो उन्हें काफी मुनाफा होगा।

गाजियाबाद में पीएम किसान योजना के 20 हजार अटके मामलों का जल्द होगा निपटारा, लगेंगे खास शिविर



गाजियाबाद। जिले में पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ई-केवाइसी के लंबित मामलों का निस्तारण करने के लिए शिविर का आयोजन ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 5,832 लैंड सीडिंग, 6,104 आधार सीडिंग और 8,272 ई-केवाईसी के मामले लंबित हैं। इनके निस्तारण के लिए कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनसेवा केंद्र संचालकों को ई-केवाईसी कराने तथा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कर्मचारियों को किसानों के नए खाते खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों को खास सलाह

राजस्व ग्रामों में संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहकर किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। किसानों से अपील की है कि यदि उनकी लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग या ई-केवाईसी लंबित है तो संबंधित कर्मचारी से संपर्क कर 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करा लें, ताकि आगामी किस्त का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

क्या है पीएम किसान योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसे पीएम किसान योजना भी कहा जाता है, यह भारत सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। इस योजनाको मुख्य तौर पर किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत हर किसान परिवार को हर साल 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस राशि को तीन किस्तों में सीधा किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है. हालांकि इस योजना के लाभ के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

ब्रज की मिठास से अवध के शाही जायके तक, गाजियाबाद में 9 अक्टूबर को सजेगा यूपी के स्वाद का संगम



गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का स्वाद किसी एक शहर या व्यंजन तक सीमित नहीं है। यदि आप ब्रज की मिठास, अवध के शाही जायके, पूर्वांचल के पारंपरिक पकवान, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के देसी व्यंजन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खान-पान का स्वाद एक ही स्थान पर चखना चाहते हैं तो आपके पास एक अद्भुत अवसर है। शुक्रवार 9 अक्टूबर को कौशांबी स्थित होटल रेडिसन ब्लू में ये सारे जायके एक साथ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। प्रदेश की समृद्ध खान-पान की परंपरा, संस्कृति और खाद्य उद्यमिता को सामने लाने के लिए दैनिक जागरण की ओर से आगरा, कानपुर, अलीगढ़, बरेली, वाराणसी और प्रयागराज के बाद अब गाजियाबाद में ह्यटेस्ट आफ उत्तर प्रदेशह्ण का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश के छह प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों अवध, ब्रज, पूर्वांचल, रुहेलखंड, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास व्यंजनों और स्थानीय स्वाद की झलक देखने को मिलेगी। आयोजन में पारंपरिक व्यंजनों के साथ ही स्थानीय खाद्य उत्पादों और नए खाद्य ब्रांडों को भी मंच मिलेगा। इसमें स्थानीय उत्पाद को वैश्विक स्तर पर कैसे ले जाएं और उत्पाद की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करें कि वो लोगों के लिए सुरक्षित हो, इन विषयों पर विशेषज्ञ विचार-विमर्श करेंगे। गाजियाबाद के बाद यह आयोजन मुरादाबाद में प्रस्तावित है, जिसके बाद लखनऊ में कार्यक्रम का भव्य समापन किया जाएगा।

ब्रज से अवध तक दिखेगी स्वाद की विविधता

आयोजन में ब्रज के गोपाल दास पेठा, बृजवासी स्वीट्स, हाथरस की रबड़ी और अलीगढ़ के इगलास का चमचम खास आकर्षण होंगे। रुहेलखंड की मुरादाबादी दाल, खोया पेड़ा, बरेली की बर्फी और रसभरी भी स्वाद प्रेमियों को लुभाएगी। पूर्वांचल से प्रयागराज के समोसे, इमरती, गाजर का हलवा और लौंगलता शामिल होंगे। बुंदेलखंड का सोन हलवा, उरई के रसगुल्ले, लाल पेड़ा और मावे की गुझिया के साथ अवध के ठग्गू के लड्डू, शाही टुकड़ा, मैंगो बर्फी और मलाई गिलौरी भी आयोजन में प्रदेश की विविध मिठास को सामने रखेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर से मेरठ की नानखटाई, कलाकंद, मुजफ्फरनगर का गुड़, घेवर और बालूशाही जायके के केंद्र में होंगे।

खाद्य उद्यमियों को भी मिलेगा मंच: टेस्ट आफ उत्तर प्रदेश केवल खान-पान का उत्सव नहीं, बल्कि स्थानीय खाद्य उत्पादों और उद्यमियों को पहचान दिलाने की पहल भी है।

विभिन्न जगहों पर रहने वाले 6 लोगों ने की आत्महत्या नौ लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत



नोएडा। नोएडा के विभिन्न जगहों पर रहने वाले छह लोगों ने मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर लिया, जबकि नौ लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सदरपुर कॉलोनी में रहने वाले राजीव (40 वर्ष) पुत्र मिथलेश मूल निवासी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार ने बीती रात को अपने घर पर मानसिक तनाव के चलते पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है।

उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के बरौला गांव में रहने वाले राजू (42 वर्ष) पुत्र किरण पाल ने अपने किराए के मकान में बीती रात को अज्ञात कारण से पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के असगरपुर गांव में रहने वाले वाली सायरा बानो (24 वर्ष) पत्नी सादिक मलिक ने बीती रात को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उन्होंने बताया कि महिला की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी। अपर पुलिस उपायुक्त की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जनपद बुलंदशहर के जहांगीरपुर के रहने वाले अंकित (26 वर्ष) पुत्र सुखपाल ने मानसिक तनाव के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। उनको उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना बीटा- दो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना फेस -वन क्षेत्र के नया बांस गांव में रहने वाले अफजल 28 वर्ष पुत्र मोहम्मद निजामुद्दीन ने बीती रात को मानसिक तनाव के चलते अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि थाना बिसरख क्षेत्र के एक सोसाइटी में रहने वाले मयंक गुप्ता (34 वर्ष) पुत्र राजेश गुप्ता ने बीती रात को अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना दादरी क्षेत्र के कस्बा दादरी में रहने वाले टीपू सुल्तान (28) पुत्र मुन्नी की बीती रात को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। थाना बिसरख क्षेत्र में रहने वाले पुलकित गौतम (26 वर्ष) पुत्र रोशन लाल निवासी गौर सिटी की बीती रात को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के छलेरा गांव में रहने वाले संजय कुमार (30 वर्ष) पुत्र ओमप्रकाश की बीती रात को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। थाना बीटा-2 क्षेत्र में रहने वाले अखिलेश (25 वर्ष) पुत्र हरपाल सिंह की बीती रात को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले दिनेश उर्फ गुड्डू (40) की बीती रात को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।

ग्रेटर नोएडा हादसे ने खोली पोल, 18 चालान कटने के बाद भी बेधड़क दौड़ रही थी बस



ग्रेटर नोएडा। आए दिन माल लादकर सड़कों पर दौड़ रही बसों पर कार्रवाई के नाम पर जिम्मेदार सिर्फ खानापूर्तिकी जा रही है। इसका एक और उदाहरण मंगलवार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आग लगी बस में देखने को मिल गया। इस बस का संचालन दिल्ली से बिहार के बीच यातायात नियमों की अनदेखी के साथ किया जा रहा था, लेकिन कार्रवाई महज यातायात चालान काटने तक सीमित रही।

बस पर कुल 18 चालान

बस के संचालन में नियमों की अनदेखी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन परिवहन एप पर इस बस के खिलाफ 18 चालान दिख रहे हैं। जिसकी कुल रकम लगभग 1,71,500 रुपये बताई जा रही है। हालांकि परिवहन विभाग के अनुसार बस में 36 चालान कटे होना बताया जा रहा है। इनमें से अधिकतर चालान परमिट उल्लंघन करने पर ही काटे गए हैं, इसके बाद भी जिम्मेदारों ने बस की परमिट निरस्त करने या सीज करने की कार्रवाई न करके सिर्फ चालान काटने तक ही सीमित रह गए और धड़ल्ले संचालक दिल्ली से बिहार रूट पर नियमों को ताख पर रखकर फरार्टा भरवाता रहा।

बस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं: बता दें कि बस के वर्ष 2026 में ही परमिट उल्लंघन के तीन चालान कटे हैं और ओवरलोडिंग करने के भी चालान कटे हुए हैं। परमिट निरस्त या सीज करने के प्रविधान होने के बाद भी सिर्फ चालान काटने तक जिम्मेदार सीमित रह गए। नियम के तहत लापरवाही बरतने पर वाहनों के खिलाफ मोटर अधिनियम की धारा 86 के तहत परमिट निरस्त करने की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद भी नियमों को उल्लंघन जारी रहने पर वाहन सीज का नियम है।

क्या कहता है नियम?

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को आग लगी बस में संचालक की ओर से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ली गई थी। इसके तहत पर्यटक वाहन देशभर में संचालित कर सकते हैं। केंद्र सरकार के 2023 के ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स परमिट नियमों का उद्देश्य वैध परमिट के आधार पर पर्यटक वाहनों का देशभर में निर्बाध संचालन है, लेकिन इसमें माल नहीं लाद सकते। इसके बाद भी नियम का उल्लंघन किया जा रहा था।

कब-कब कटा चालान?

ओवरलोडिंग के मामले में सात सितंबर को 31 हजार रुपये का चालान कटा।

22 जुलाई को 17.500 रुपये का चालान कटा।

ग्रेटर नोएडा में टैक्स बचाने का खेल बना जानलेवा, स्लीपर बसों में यात्रियों के साथ लादा जा रहा सामान

जेवर (ग्रेटर नोएडा)। यात्रियों को ढोने वाली डबल डेकर स्लीपर बसों में टैक्स बचाने के लिए सामान लादने का खेल उनकी जान पर भारी पड़ रहा है। जेवर में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण बस अग्निकांड में नौ यात्रियों की मौत के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान से प्रशासन हरकत में आया। 28 से 30 सितंबर आपरेशन कवच 2.0 चलाकर स्लीपर बसों की सघन जांच की गई, लेकिन अभियान थमते ही एक्सप्रेसवे पर फिर वही हालात लौट आए।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक और डबल डेकर स्लीपर बस में आग लग गई। बस में सवार 35 यात्रियों और लाखों को समान भरा हुआ था लेकिन चालक की सूझबूझ से यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर 24 सितंबर को हुए बस अग्निकांड में नौ यात्री जिंदा जल गए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद नियमों को ताक पर रख दौड़ रही स्लीपर बसों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई हुई। सूत्रों की माने तो अभियान लांच होने के साथ ही नियमों को रौंदते हुए दौड़ने वाली बसों के संचालकों ने अपनी बसों को सड़कों से हटाकर साइड कर दिया। लेकिन जैसे ही मामला शांत हुआ फिर से उसी पुराने ढर्रे पर बसों को दौड़ना शुरू हो गया।

यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद बसों की फिटनेस, परमिट, अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन निकास के साथ यात्रियों के बीच व्यावसायिक सामान की ढुलाई भी सवालों के घेरे में आई थी। आरोप है कि टैक्स और परिवहन खर्च बचाने के लिए सामान स्लीपर बसों के जरिये भेजते हैं। जबकि ज्वलनशील या अधिक मात्रा में सामान आग लगने की स्थिति में यात्रियों के लिए खतरा बनता है।

एक गाड़ी के 82 ट्रैफिक चालान, 4.98 लाख रुपये बकाया; पिता-पुत्र के डीएल पर लटकी तलवार

पश्चिमी दिल्ली। बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पश्चिम जिला ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। एक वाहन से जुड़े 82 यातायात उल्लंघनों के मामले में पिता-पुत्र के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) को पत्र भेजा गया है। वाहन पर करीब 4.98 लाख रुपये के चालान बकाया हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, संबंधित वाहन का पहला यातायात उल्लंघन 28 नवंबर 2023 को दर्ज किया गया था, जबकि 82वां उल्लंघन 19 अगस्त को दर्ज हुआ। इस तरह वाहन के खिलाफ कुल 82 उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। पश्चिम जिला ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त रणबीर सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान वाहन के पंजीकृत मालिक रामदास अहिरवार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत नोटिस जारी किया गया। सरकारी रिकार्ड में दर्ज दिल्ली का पता और मोबाइल नंबर बदल चुके थे। रामदास मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा क्षेत्र स्थित गांव गदारी के निवासी हैं। नोटिस के जवाब में रामदास ने बताया कि वह पहले वाहन चलाते थे, लेकिन पिछले करीब एक वर्ष से उनका बेटा मोहित कुमार अहिरवार वाहन चला रहा था। इस अवधि में हुए यातायात उल्लंघनों के दौरान भी वाहन उनके बेटे के चलाने की जानकारी दी गई। पश्चिम जिला ट्रैफिक पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) नीरज कुमार के निर्देश और सिफारिश पर दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में कार्रवाई के लिए टीकमगढ़ के जिला परिवहन अधिकारी को अनुरोध भेजा गया है। पुलिस ने लाइसेंसिंग प्राधिकरण से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के तहत दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या अयोग्य घोषित करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त ने कहा कि बार-बार यातायात नियम तोड़ने वालों की पहचान कर वाहन मालिकों और चालकों की जवाबदेही तय करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।

अर्थव्यवस्था की ताकत-समृद्धि का आधार है 'अन्नदाता': योगी



लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद कृषि क्षेत्र में आए अभूतपूर्व परिवर्तन से प्रदेशवासियों को अवगत कराया। उन्होंने अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार भी बताया।

किसान को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार आज अन्नदाता किसान को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2017 से पहले जो अन्नदाता किसान कर्ज, बदहाली व लाचारी में डूबा रहता था और बिचौलियों के चक्कर लगाने को मजबूर था, आज वही अन्नदाता किसान कर्ज से मुक्त होकर उन्नत बीज, सिंचाई, और डीबीटी के माध्यम से एमएसपी एवं पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहा है।

8 से बढ़कर 18 प्रतिशत हुई कृषि विकास दर : मुख्यमंत्री ने बताया कि दशकों से लटकी सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं। प्रदेश, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हुई है। दुग्ध, गन्ना, गेहूं आदि के उत्पादन में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है।

धान किसानों को किया गया 1,03,833 करोड़ से अधिक का भुगतान : मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्नदाता किसान की मेहनत का सम्मान एवं उसकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई और ?1,03,833 करोड़ से अधिक का सीधा भुगतान किया गया। उसी प्रतिबद्धता के साथ इस बार भी धान के समर्थन मूल्य में 71 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

नीलामी चबूतरों, दुकानों और नालियों पर ज्यादा ध्यान

इस अभियान के अंतर्गत मंडी परिसर में स्थित नीलामी चबूतरों के आसपास की नालियों में जमा कूड़े को हटाने तथा चबूतरों और उनसे संबंधित संरचनाओं की सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन स्थानों पर नमी रहती है, वहां कूड़ा हटाने के बाद निदेर्शानुसार चूना पाउडर अथवा गैमक्सीन का छिड़काव कराया जाएगा।

शौचालयों और किसान विश्राम गृहों में सुविधाओं पर रहेगा ध्यान

मंडी परिसरों में बने शौचालयों, प्रसाधनों और यूरिनल की सफाई के साथ जलापूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शौचालयों के आसपास जलभराव वाले स्थानों की विशेष सफाई कर वहां नियमित रूप से चूने का छिड़काव कराया जाएगा। कार्यालय भवनों और किसान विश्राम गृहों की साफ-सफाई तथा आवश्यक साज-सज्जा पर भी ध्यान दिया जाएगा। मंडी परिसरों में जहां नए सिविल, विद्युत अथवा मरम्मत संबंधी कार्य चल रहे हैं, उन स्थलों को अलग से चिह्नित किया जाएगा।

निर्माण कार्य के बाद बची अनुपयोगी सामग्री और मलबे को भी अभियान के दौरान हटवाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश की मंडियों में चलेगा 15 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान, साफ-सफाई से बदलेगी तस्वीर : योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन मंडियों में साफ-सफाई की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा किसानों को स्वच्छ एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्वच्छ मंडी-शुभ मंडी अभियान-2026 संचालित करने का निर्देश दिया है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद ने अक्टूबर, 2026 में प्रदेश की सभी मंडी एवं उपमंडी स्थलों पर व्यापक स्तर पर विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

इस अभियान के तहत मंडी परिसरों में जमा कूड़े, बंद नालियों, जलभराव वाले स्थानों, शौचालयों, नीलामी चबूतरों, दुकानों और किसान विश्राम गृहों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस अभियान के दौरान मंडी समितियों के अनुबंधित सफाई ठेकेदारों को अपने सभी सफाई कर्मियों को लगाकर युद्धस्तर पर सफाई कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंडी परिसर के प्रत्येक हिस्से की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। विशेष रूप से नालियों में फंसे अपशिष्ट तथा पानी जमा होने वाले स्थानों को चिह्नित कर उनकी सफाई कराई जाएगी।

केदारनाथ पैदल मार्ग बंद: चीरबासा में मलबा-पत्थर आने से रास्ता हुआ अवरुद्ध , गौरीकुंड में रोके यात्री



रुद्रप्रयाग : केदारनाथ पैदल मार्ग पर शनिवार सुबह चीरबासा में मलबा और पत्थर आने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने गौरीकुंड में यात्रियों को रोक दिया है। मार्ग खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की टीम मजदूरों की मदद से मलबा हटाने में जुटी है। मौके पर पुलिस बल और रेस्क्यू टीम भी मौजूद है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि शनिवार सुबह 7:22 बजे सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड से चीरबासा में मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना मिली। इसके बाद संबंधित विभागों को तत्काल सूचित किया गया। मार्ग से मलबा और पत्थर हटाने का काम किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रास्ता सुचारू होने तक उन्हें गौरीकुंड में ही रोका गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर आपदा कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है और यात्रियों से सुरक्षा निदेर्शों का पालन करने और मार्ग खुलने तक आगे न बढ़ने को कहा जा रहा है।

देहरादून दरगाह तोड़फोड़: खादिम पर हथौड़े और लाठी-डंडे लेकर टूट पड़े 25 लोग, बंधक बनाकर पीटा

देहरादून। डालनवाला क्षेत्र स्थित रेंजर्स ग्राउंड में दरगाह बाबा जमात शाह में घुसकर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि दरगाह के खादिम को बंधक बनाकर मारपीट की गई। शिकायत पर पुलिस ने बजरंग दल के दो कार्यकताओं को नामजद करते हुए 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में दरगाह के खादिम मकसूद अहमद ने शिकायत की। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दरगाह बाबा जमात शाह में बजरंग दल के अमन स्वेडिया, सिद्धार्थ अपने 20-25 साथियों के साथ हथौड़े, लाठी डंडे के साथ जबरन दरगाह परिसर में घुसकर तोडफोड की। आरोप है कि सभी ने मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान बुजुर्ग खादिम को भी बंधक बनाकर मारपीट की गई। शिकायत में आरोप लगाया कि जानबूझकर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपित अमन स्वेडिया, सिद्धार्थ बड़ोनी को नामजद करते हुए 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

साइबर ठगी के नए-नए तरीके: पुलिस का हाईटेक तंत्र, फिर भी दो कदम आगे ठग

आगरा : पुलिस का तंत्र हाईटेक है फिर भी ठग लगातार मालामाल हो रहे हैं, वहीं अपनी गाढ़ी कमाई गंवाने वाली जनता बेहाल है। पिछले 9 महीने 10 दिन में 19 करोड़ से अधिक रुपये साइबर अपराधी लूट चुके हैं। इसके इतर पुलिस अब तक मात्र 14 फीसदी रकम ही पीड़ितों को दिला सकी है। बाकी 86 फीसदी रकम या तो खातों से निकल गई या फिर खातों में पड़ी होने के बावजूद पीड़ितों को नहीं मिल सकी है। कानपुर नगर निगम में सेवानिवृत्त लेखाकार विनोद कुमार श्रीवास्तव को डिजिटल अरेस्ट किया गया। एटीएस का अधिकारी बनकर उनकी गाढ़ी कमाई के 72.74 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। उन्हें रकम वापसी का इंतजार है। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी डिजिटल अरेस्ट, निवेश में मुनाफे का लालच देकर और ग्रीन गैस का बिल अपडेट करने के नाम पर साइबर अपराधी लोगों के खाते से रकम उड़ा चुके हैं।

लोग कैसे-क्यों बन जाते हैं शिकार?: पुलिस के मुताबिक, वर्तमान में ऑनलाइन खरीदारी का दौर है। अधिकतर लोग अपने मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, घर का पता अलग-अलग एप पर शेयर करते हैं। साइबर अपराधी इसी का फायदा उठाते हैं। विभिन्न मॉल, कंपनियों, मोबाइल व सिम की दुकानों, साइबर कैफे आदि से जुड़े डाटा कभी चुराकर तो कभी मिलीभगत से हासिल कर लेते हैं। कई बार अलग-अलग इलाकों में बैठे साइबर अपराधी टेली कॉलिंग से लोगों को भी शिकार बनाते हैं। कभी बीमा-निवेश के नाम पर ठगते हैं तो कभी गिरफ्तारी का डर दिखाकर। इतना ही नहीं रिवार्ड पॉइंट, नौकरी का झांसा, घर बैठे कमाने का प्रलोभन भी इनका हथियार है। पेंशन दिलाने, बिजली बिल ठीक कराने, केवाईसी कराने, ग्रीन गैस का बिल अपडेट कराने की कहकर भी ठग रहे हैं।

झारखंड-महाराष्ट्र से कॉल, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश के खाते डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी दो तरीके से ठग रहे हैं। एक तो लालच देते हैं, दूसरा डर दिखाते हैं। दोनों ही मामलों में जागरूकता के अभाव में वारदात होती है। पुलिस के पास साइबर धोखाधड़ी के 100 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने जिन नंबरों से कॉल किए गए, जिन खातों में रकम गई, उनकी जांच की। सामने आया कि कॉल झारखंड और महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों से किए गए थे जबकि खाते दिल्ली, मध्य प्रदेश और यूपी के बैंकों के थे। डिजिटल अरेस्ट के मामले में लोग काफी दिन बाद शिकायत दर्ज कराते हैं। तब तक रकम आरोपी निकाल लेते हैं।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार है 'अन्नदाता': मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद कृषि क्षेत्र में आए अभूतपूर्व परिवर्तन से प्रदेशवासियों को अवगत कराया। शनिवार को उन्होंने अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार भी बताया। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार आज अन्नदाता किसान को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2017 से पहले जो अन्नदाता किसान कर्ज, बदहाली व लाचारी में डूबा रहता था और बिचौलियों के चक्कर लगाने को मजबूर था, आज वही अन्नदाता किसान कर्ज से मुक्त होकर उन्नत बीज, सिंचाई, और डीबीटी के माध्यम से एमएसपी एवं पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दशकों से लटकी सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं। प्रदेश, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हुई है। दुग्ध, गन्ना, गेहूं आदि के उत्पादन में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्नदाता किसान की मेहनत का सम्मान एवं उसकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई और 1,03,833 करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान किया गया। उसी प्रतिबद्धता के साथ इस बार भी धान के समर्थन मूल्य में 71 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार के लिए अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार बताया।

उन्होंने कहा कि इसीलिए अन्नदाता किसान के अधिकार की रक्षा और उसकी खुशहाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कातिल पत्नी और प्रेमी का बदलेगा ठिकाना; मुस्कान होगी यहां शिफ्ट

मेरठ : मेरठ के ब्रह्मपुरी के चर्चित नीले ड्रम वाला सौरभ हत्याकांड की आरोपी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला को अदालत से दोषी करार दिया जा चुका है। इसके अलावा बहसूमा के अकबरपुर सादात के अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी रविता और उसका प्रेमी अमरदीप भी दोषी करार दिए जा चुके है। साहिल, अमरदीप सजा होने के बाद आगरा सेंट्रल जेल जाएंगे जबकि मुस्कान और रविता लखनऊ नारी बंदी निकेतन में जाएगी। हालांकि अभी करीब एक साल लगेगा, जब दोषी सेंट्रल जेल में जाएंगे। सेंट्रल जेल में दोषियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहां से वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा लखनऊ शासन में रिपोर्ट भेजेंगे।

वहीं, सांप कांड में रविता और अमरदीप को दोषी पाया गया है। दोनों को 16 अक्तूबर को सजा सुनाई जानी है। सजा को लेकर सभी दोषियों का डर सता रहा है। डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि सजा होने के बाद पुरुष कैदी को आगरा सेंट्रल जेल भेजा जाता है जबकि महिला कैदी को लखनऊ में नारी बंदी निकेतन भेजा जाता है।

36 घंटे बाद इस हालत में मिला हरिद्वार में लापता हुआ ड्रोन, पेलोड और अत्याधुनिक कैमरों से लैस...



हरिद्वार। अर्द्धकुंभ की तैयारियों के लिए लाया गया ड्रोन आखिरकार 36 घंटे बाद मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों में मिल गया। एक दूसरे ड्रोन की मदद से खुद कर्मचारियों ने इसे ढूंढ़ लिया। जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करके ड्रोन को खोज लिया गया। ड्रोन मिलने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। बता दें कि अर्द्धकुंभ की तैयारियों के लिए मंगाया गया ड्रोन उड़ान भरते ही सुबह लापता हो गया। ड्रोन की कीमत 40 लाख रुपए बताई गई थी। साथ ही शहर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आईआईटी रुड़की के कर्मचारी शिवम नौटियाल की ओर से मिसिंग दर्ज कराई गई थी। अर्द्धकुंभ के लिए मैपिंग जैसे कार्यों के लिए आईआईटी रुड़की से यह ड्रोन हरिद्वार मंगाया गया था। उड़ान भरने के बाद ड्रोन लापता हो गया। ड्रोन की आखिरी लोकेशन उत्तर हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में पाई गई थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से मैपिंग और अन्य कार्यों के लिए करीब 40 लाख रुपए में ड्रोन इस्तेमाल में लाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को भूपतवाला क्षेत्र में करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ान भर रहा था। इस दौरान उसका कंट्रोल से संपर्क टूट गया। इससे हड़कंप मच गया। पुलिस की शुरूआती छानबीन में सामने आया था कि आईआईटी रुड़की के दो कर्मचारी ड्रोन उड़ा कर खाना खाने चले गए थे। करीब एक घंटे बाद खाना खाकर वापस लौटे तो ड्रोन गायब था। काफी प्रयास के बावजूद ड्रोन से संपर्क नहीं हो पाया। ड्रोन का बैटरी बैकअप चार से छह घंटे बताया गया था। इसी भरोसे कर्मचारी ड्रोन को उड़ाकर खाना खाने गए थे।

उत्तराखंड के टीचरों का दुनिया में डंका: स्टैनफोर्ड की लिस्ट में इस कॉलेज के 52 शिक्षक, कुलपति की भारत में पहली रैंक



देहरादून। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के 52 शिक्षकों ने दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकताओं ने एल्सेवियर के सहयोग से यह सूची तैयार की है।विश्वविद्यालय के कुलपति डा. नरपिंदर सिंह को करियर के अब तक के शोध के आधार पर भारत में पहली रैंक मिली है।

दो विषयों में भारत में पहली रैंकिंग

डा. नरपिंदर सिंह ने कृषि, मत्स्य एवं वानिकी में विश्व स्तर पर 116वीं और खाद्य विज्ञान में 55वीं रैंक हासिल की है। इन दोनों विषयों में उनकी भारत में पहली रैंकिंग है। यह उपलब्धि कृषि और खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में उनके शोध योगदान को दशार्ती है। सूची में शामिल अन्य शिक्षकों में डा अजमल हुसैन, डा. ए कर्णवाल, डा. मोहित बजाज, डा. जी मुरली, डा. मोहम्मद वाजिद, डा. मनोज दिवाकर, डा. मनु शर्मा, डा. अजय सिंह वर्मा, डा. विनय कुमार पांडेय, डा. संदीप गुप्ता, डा. मंगे राम और डा. राकेश कुमार समेत अन्य शिक्षक शामिल हैं।

सीजेपी प्रदर्शन: देहरादून से दिल्ली जाने वाले लोग परेशान, काठगोदाम से कोई ट्रेन कैंसिल नहीं



देहरादून। दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए आज यानि शनिवार सुबह पांच बजे देहरादून से दिल्ली जाने वाली ट्रेन जन शताब्दी के संचालन पर रोक लगाई गई। जिस कारण देहरादून से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। देहरादून से अन्य ट्रेनें समयसारिणी के अनुसार संचालित की जा रही हैं। वहीं काठगोदाम से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई है। स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए देहरादून रेलवे प्लेट फार्म से सुबह पांच बजे दिल्ली के लिए संचालित की जाने वाली ट्रेन जन शताब्दी के संचालन पर रोक लगाई गई है। जबकि अन्य ट्रेनों का संचालन निर्धारित समय पर होगा।

योगी सरकार ने बाढ़ से 25.59 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के खतरे से आबादी और कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए योगी सरकार ने बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को गति दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक अब तक लगभग 1,549 बाढ़ परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन कार्यों के माध्यम से 25.59 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बचाने के साथ 2.21 करोड़ से अधिक आबादी को लाभान्वित किया गया है। बाढ़ सुरक्षा के इन इंतजामों से किसानों की जमीन, ग्रामीण आबादी और खेती-किसानी से जुड़ी आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिली है।



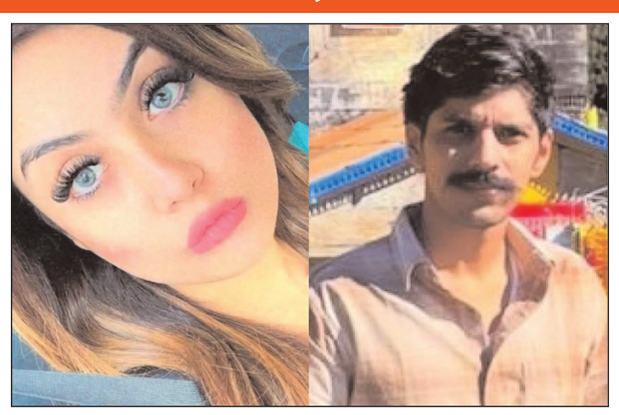
25.59 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सुरक्षा: सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुताबिक प्रदेश में बाढ़ से बचाव के लिए पूरी की गई परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ के प्रभाव को कम करना और आबादी व कृषि भूमि को सुरक्षित रखना है। 25.59 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का संरक्षण किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाढ़ से खेतों में खड़ी फसल, उपजाऊ जमीन और कृषि गतिविधियों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। ऐसे में बाढ़ सुरक्षा के कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की सुरक्षा को मजबूती मिली है।

2.21 करोड़ आबादी को मिला लाभः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिहाज से भी इन परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2.21 करोड़ से अधिक आबादी को लाभ मिलने से बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा के प्रयासों को बल मिला। बाढ़ से घरों, ग्रामीण संपर्क मार्गों और स्थानीय जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए बाढ़ सुरक्षा संबंधी कार्यों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश में जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 1,300 सिंचाई परियोजनाएं भी पूरी की गई हैं।

शिवा के जिस्म पर लिपस्टिक और बर्बरता के निशान, सचिवालय पास लगी ऑडी कार से गहराया सस्पेंस

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में हजरतगंज इलाके के बालू अड्डा के पास स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे तल से रहस्यमय हालात में गिरने से हुई चिकन कारोबारी शिवा की मौत के मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले उसके शरीर पर 10 गंभीर चोटें मिली हैं। माना जा रहा है कि उसके साथ बर्बरता की गई थी। शिवा की मां रंजना का आरोप है कि श्रद्धा, उसकी बहन और अन्य आरोपियों ने पहले बेटे की जमकर पिटाई की और फिर चौथे तल से नीचे फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, शिवा के शरीर पर जो चोटें लगी थीं, उनके कारण ज्यादा खून बह गया। इससे सदमा लगा और उसकी मौत हो गई। शिवा के शरीर पर सभी चोटें उनके जिंदा रहते लगी थीं। मौत के बाद एक भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। शिवा को किसी कठोर वस्तु से चोट पहुंची थी। आरोप है कि चौथे तल से फेंकने के कारण शिवा फर्श से टकराया था। इससे शरीर पर रगड़ के निशान मिले हैं। हालांकि, रिपोर्ट में चोट लगने और मौत के बीच का समय स्पष्ट नहीं हो सका है। इसी बीच फोरेंसिक टीम ने रविवार को साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने फ्लैट में रहने वाले लोगों के बयान लिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिवा अर्द्धनग्न अवस्था में था और उसके शरीर पर लिपिस्टिक के निशान थे।

नेता, ब्यूरोकेट्स से थे संबंध,



शिवा को देती थी धमकी

रंजना के मुताबिक, श्रद्धा के कई नेताओं, ब्यूरोकेट्स और खिलाड़ियों से संबंध थे। सोशल मीडिया पर कई लोगों के साथ श्रद्धा की फोटो भी वायरल हो रही है। आरोप है कि श्रद्धा अपनी पहुंच का रौब दिखाकर शिवा को जेल भिजवाने की धमकी देती थी। शिवा विभूतिखंड में एक कैफे के बाहर गोली चलाने के आरोप में पहले जेल जा चुका था। इसके कारण वह दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था। इसी बात का फायदा उठाकर श्रद्धा उसे ब्लैकमेल करती थी।

विज्ञापन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि दोनों साथ में हैं, जबकि अन्य आरोपियों की लोकेशन अलग मिली है। पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। एक टीम श्रद्धा के मूल जनपद रायबरेली में डेरा डाले है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस आरोपियों के मददगारों का भी पता लगा रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से भी अहम सुराग मिले हैं।

फुटेज से कड़ी जोड़ रही पुलिस, किसकी थी ऑडी कार

पुलिस ने अवध ग्रीन अपार्टमेंट व उसके आसपास लगे फुटेज खंगाले हैं। फुटेज में घटना के 15 मिनट बाद एक सफेद रंग की ऑडी कार वहां आती हुई दिखी। कार पर सचिवालय का पास लगा है। कार वहां आने के बाद फिर वापस चली जाती है। पुलिस फुटेज के जरिए कड़ियां जोर रही है। सीसीटीवी में आरोपी भी कैद हुए हैं। एसीपी रजनीश वर्मा का कहना है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद घटनाक्रम का पता चल सकेगा। फिलहाल सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार शाम को सेक्टर एफ अलीगंज निवासी शिवा शर्मा 28 की रहस्यमय हालात में प्रेमिका श्रद्धा के फ्लैट से गिरकर मौत हो गई थी।

कैंची धाम स्पेशल ट्रैफिक प्लान: साढ़े बारह बजे तक सात हजार श्रद्धालु पहुंचे, क्यूआरटी टीम मुस्तैद

गरमपानी। वीकेंड पर पुलिस के विशेष यातायात व्यवस्था का असर हाईवे व कैंची धाम में दिखना शुरू हो गया। जहां एक ओर अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर स्थित तमाम बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है वहीं पिछले दिनों की अपेक्षा कैंची धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ सीमित हो गई। साढ़े बारह बजे तक साढ़े सात हजार श्रद्धालुओं ने बाबा के दर पर शीश झुकाए। पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के साथ ही क्यूआरटी के जवान भी कैंची क्षेत्र में डटे हुए हैं। कैंची से आगे के बाजार क्षेत्रों में सन्नाटा पसर जाने से व्यापारियों मायूस हैं। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर स्थित सुप्रसिद्ध कैंची धाम आश्रम में हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को देख पुलिस ने इस वीकेंड विशेष यातायात प्लान लागू किया है। पिछले दिनों भारी संख्या में भीड़ पहुंचने से यातायात व्यवस्था पटरी से उतर गई थी। जाम के कारण हाईवे पर आवाजाही करने वाले यात्रियों व पर्यटकों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनिवार के लिए यातायात प्लान जारी होने के बाद हाईवे पर सन्नाटा पसरा रहा। भवाली से शटल सेवा के जरिए श्रद्धालु कैंची धाम पहुंचे। दोपहर साढ़े बारह बजे तक साढ़े सात हजार श्रद्धालुओं ने आश्रम में प्रवेश किया। पुलिस के कई आला अधिकारियों भी सुबह से ही कैंची क्षेत्र में डट गए। पहली बार क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) की तैनाती भी कैंची क्षेत्र में की गई है। हाईवे पर यातायात व्यवस्था भी सामान्य बनी हुई है।

जिले की मंडियों में 1.93 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद, उठान में तेजी लाने पर दिया जा रहा जोर



कैथल। जिले की विभिन्न अनाज मंडियों में धान की आवक और सरकारी खरीद प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। किसानों की सुविधा और धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। डीसी अपराजिता के निदेर्शानुसार खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदने के साथ-साथ खरीदे गए धान का समय पर उठान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। 9 अक्टूबर तक जिले की विभिन्न मंडियों में कुल 1,93,684 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। वहीं, 46,162 मीट्रिक टन धान का उठान किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि मंडियों में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और खरीद एवं उठान की प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से जारी रहे। जिले में धान खरीद के कार्य में विभिन्न सरकारी एजेंसियां जुटी हुई हैं। आंकड़ों के अनुसार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 95,234 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इसी प्रकार हैफेड द्वारा 64,642 मीट्रिक टन तथा हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 33,808 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। सभी एजेंसियों के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले की सभी मंडियों में धान की खरीद का कार्य जारी है। अरनौली में 2,511 मीट्रिक टन, भागल में 2,243 मीट्रिक टन, ढांड में 32,329 मीट्रिक टन, धनौरी में 122 मीट्रिक टन, गुहला चीका की पुरानी मंडी में 18,210 मीट्रिक टन तथा नई मंडी में 29,143 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। इसी प्रकार कैथल की पुरानी मंडी में 2,816 मीट्रिक टन, नई मंडी में 17,947 मीट्रिक टन, अतिरिक्त मंडी में 27,939 मीट्रिक टन, कलायत में 3,808 मीट्रिक टन, कांगथली में 516 मीट्रिक टन, कौल में 4,421 मीट्रिक टन, पाई में 3,607 मीट्रिक टन तथा पूंडरी में 27,017 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है।

इसके अलावा राजौंद में 2,000 मीट्रिक टन, रामथली में 3,945 मीट्रिक टन, सीवन में 7,677 मीट्रिक टन, चीका में बाबुराम राइस मिल के सामने स्थित खरीद केंद्र पर 476 मीट्रिक टन, गंगोत्री मार्बल के सामने स्थित खरीद केंद्र पर 852 मीट्रिक टन तथा अदानी एग्रो साइलो, ढांड में 6,105 मीट्रिक टन धान की खरीद दर्ज की गई है।

खरीद और उत्थान कार्य में और तेजी लाएं एजेंसी

डीसी अपराजिता के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडियों में व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के लिए खरीदे गए धान का समय पर उठान करवाएं। इसके तहत खरीद एजेंसिया खरीद प्रक्रिया में और तेजी लाएं। मंडियों में धान की आवक के अनुरूप खरीद और उठान का कार्य लगातार चलता रहे, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

भट्ठूकलां में संयुक्त मोर्चे का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका

फतेहाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर शनिवार को अखिल भारतीय किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और सीटू के बैनर तले भट्ठू मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की नीतियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभाष चंद्र भादु ने की, जबकि मंच संचालन व मुख्य वक्ता की भूमिका किसान सभा के जिला प्रधान विष्णु दत्त तथा रोहतास डूडी ने निभाई।

किसान सभा के जिला प्रधान विष्णु दत्त ने कहा कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों का पुलिस-प्रशासन आम नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोक रहा है।

सार संक्षेप

क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोपित गिरफ्तार



जींद। आर्थिक अपराध शाखा जींद तथा थाना शहर जींद पुलिस की संयुक्त टीम ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से दो लाख रुपये भी बरामद किए हैं। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। आर्थिक अपराध शाखा जींद के अनुसंधान अधिकारी उपनिरीक्षक जयवीर सिंह ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि संत नगर निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि बुल रन वे नामक कंपनी के संचालकों एवं उनके सहयोगियों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश करवाने के नाम पर लोगों को अधिक मुनाफा देने का लालच दिया और उनकी निवेश की गई राशि वापस नहीं लौटाई। उसने बताया कि कंपनी से जुड़े व्यक्तियों ने लोगों को विश्वास दिलाया था कि उनके द्वारा निवेश की गई राशि पर प्रतिदिन एक प्रतिशत तक ब्याज दिया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में उनकी रकम दोगुनी हो जाएगी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी की योजनाओं का प्रचार किया गया था और बैठकों एवं सेमिनारों के माध्यम से लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिसमें सुरेंद्र कुमार, राजेंद्र, सतनाम सिंह, सुल्तान सिंह, सत्यपाल तथा सरोज बाला के काफी रुपये निवेश के नाम पर लिए गए थे। इसके बाद निवेश की मूल राशि वापस नहीं मिलने पर पीड़ितों को धोखाधड़ी का संदेह हुआ। जिसकी शिकायत के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा जींद व थाना शहर जींद की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। मामले की जांच के दौरान संबंधित बैंक खातों के रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की जांच की। बैंक खातों की जांच में सामने आये तथ्यों के आधार पर संगरूर (पंजाब) निवासी बूटा सिंह व बरनाला (पंजाब) निवासी गुरमीत सिंह को नियमानुसार गिरफ्तार करके प्रत्येक से एक-एक लाख रुपये बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपितों को माननीय अदालत में पेश कर आगामी कार्रवाई नियम अनुसार अमल में लाई जा रही है। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि जींद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई नियम अनुसार अमल में लाई जा सके।

वोटों में कथित हेराफेरी और मतदाता अधिकारों पर हमले के विरोध में किया प्रदर्शन



जींद। वोटों में कथित हेराफेरी और मतदाता अधिकारों के सवाल पर सीटू कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जींद के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले का दहन किया और उनको पद से बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीटू के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र ने कहा कि भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपनी राजनीतिक जरूरतों के अनुसार करवाई और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बडि?ों के जरिये सत्ता हासिल की। उन्होंने 14 करोड़ वोट काटे जाने और बड़े पैमाने पर कथित हेराफेरी के आरोप लगाते हुए कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के वोट की अहमियत सर्वोपरि है। यदि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो उनकी पारदर्शी जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

पुलिस से मुठभेड़ में इनामी नशा तस्कर सहित तीन बदमाश काबू

मार्फत पर लड़ाई-झगड़ा, चोरी, जाली करेंसी और एनडीपीएस के चार केस, फूल बाबू पर एनडीपीएस के दो केस और श्रीकुल पर एनडीपीएस का एक केस दर्ज है। पुलिस ने थाना सेक्टर-65 में जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



गुरुग्राम। स्थानीय पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर-65 की टीम ने लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे तीन हथियारबंद बदमाशों को शुक्रवार की देर रात मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उनके कब्जे से 136 ग्राम एमडीएमए, एक पिस्टल, एक देशी कट्टा और खाली खोल बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार नौ अक्टूबर की रात को सूचना मिली थी कि तीन हथियारबंद युवक लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस पर पुलिस ने नंगली उमरपुर से सेक्टर-62 की ओर जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की। रात करीब 11 बजे बाइक पर सवार तीन युवक आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो आरोपियों ने बाइक भगाने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पीछा कर उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने लगातार छह गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली पुलिस वाहन पर लगी और एक गोली एक पुलिस कर्मचारी की बाजू पर लगी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में तीन गोलियां चलाईं, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को काबू कर लिया। घायल पुलिसकर्मी और दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी मार्फत उर्फ मारू (32), फूल बाबू शेख (26) और श्रीकुल शेख (37) के रूप में हुई है। इनमें से फूल बाबू शेख पर एनडीपीएस एक्ट के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। मार्फत पर लड़ाई-झगड़ा, चोरी, जाली करेंसी और एनडीपीएस के चार केस, फूल बाबू पर एनडीपीएस के दो केस और श्रीकुल पर एनडीपीएस का एक केस दर्ज है। पुलिस ने थाना सेक्टर-65 में जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पंजाब में नशीली गोलियों की खेप सप्लाई करने जा रहा तस्कर



फतेहाबाद। मेडिकल नशे की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसते हुए रतिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने व्यावसायिक मात्रा में 9,600 नशीली गोलियों की बड़ी खेप बरामद कर एक आरोपी को दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान फतेहाबाद जिले के गांव महमड़ा निवासी खजान सिंह के रूप में हुई है। बरामद नशीली गोलियों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 7 लाख रुपये आंकी गई है। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी रतिया कुलवंत सिंह ने बताया कि एसपी निकिता खट्टर के निदेर्शानुसार नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस चौकी महमड़ा प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक ज्योति प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव ढाणी बबनपुर क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान गुप्त सूचना मिली कि गांव महमड़ा निवासी खजान सिंह, जो गांव बादलगढ़ में डॉक्टरी का कार्य करता है, नशीली गोलियों के अवैध कारोबार में संलिप्त है और इतनी बड़ी खेप लेकर पंजाब के बीरेवाला क्षेत्र में सप्लाई करने जाने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए गांव बादलगढ़ स्थित रविदास धर्मशाला के पास नाकाबंदी व निगरानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक व्यक्ति नीले व काले रंग का बैग लेकर आता दिखाई दिया, जो पुलिस वाहन को अचानक देखकर पीछे मुडकर तेज कदमों से जाने लगा।

फरीदाबाद : होटल में लटका मिला युवती का शव, युवक फरार



फरीदाबाद। फरीदाबाद के सेक्टर-11 स्थित एक होटल के कमरे में आगरा की रहने वाली 25 वर्षीय युवती अदिति का शव फंदे से लटका मिला।

युवती पिछले तीन दिन से अपने प्रेमी हेमंत शर्मा के साथ होटल में ठहरी हुई थी। पुलिस के मुताबिक, उसका प्रेमी रात में होटल से चला गया था। शनिवार की सुबह होटल स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भिजवा दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली अदिति तीन दिन पहले घर में बिना बताए फरीदाबाद आई थी। यहां वह फरीदाबाद निवासी हेमंत शर्मा के साथ सेक्टर-11 के होटल रॉयल हार्मनी के कमरा नंबर 204 में ठहरी हुई थी। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। हेमंत मूल रूप से आगरा का रहने वाला है और फिलहाल फरीदाबाद में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है।

धान खरीद में कटौती के विरोध में मार्केट कमेटियों में तालाबंदी करेंगे किसान संगठन



जींद। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान खरीद के दौरान किसानों को कथित तौर पर हो रही आर्थिक परेशानी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम भुगतान के विरोध में किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। शनिवार को नरवाना में आयोजित बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा किसान, मजदूर संघर्ष मोर्चा से जुड़े प्रतिनिधियों ने आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की विभिन्न अनाज मंडियों में धान की खरीद के दौरान किसानों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक कम भुगतान किया जा रहा है। सुमित दलाल ने उन्होंने आरोप लगाया कि खरीद प्रक्रिया में व्यापारियों, संबंधित अधिकारियों और मार्केटिंग बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसान संगठनों ने पूरे मामले की जांच कर किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य दिलाने की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से किसानों का एक-एक दाना खरीदने की बात कही जाती हैए लेकिन जमीनी स्तर पर खरीद प्रक्रिया में अनेक समस्याएं सामने आ रही हैं। जिलेवार खरीद की तारीखों में अंतर, पोर्टल संबंधी दिक्कतों और सत्यापन प्रक्रिया में देरी के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग जिलों में खरीद शुरू होने की तारीखें अलग होने और सत्यापन में देरी से मंडियों में किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। किसान नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश की कई मंडियों में हालात चिंताजनक हैं और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार और प्रशासन से खरीद व्यवस्था में तत्काल सुधार करने की मांग की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 14 अक्टूबर को हरियाणा की सभी मार्केट कमेटियों में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि धान खरीद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला तो 14 अक्टूबर को आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। किसान संगठनों ने सरकार से मांग की कि मंडियों में धान की खरीद सुचारु रूप से करवाई जाए, सत्यापन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

करनाल में 900 ग्राम वजन के साथ पैदा हुई बच्ची को गुरुग्राम में मिला जीवनदान



गुरुग्राम। मात्र 900 ग्राम वजन के साथ पैदा हुई बच्ची को यहां चिकित्सकों ने कड़ी उपचार प्रक्रिया से जीवनदान दिया। मूलरूप से करनाल के रहने वाले दंपत्ति की इस बच्ची को सांस लेने में मदद के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन, फेफड़ों को विकसित करने के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी। यह जानकारी पारस अस्पताल में नियोनेटोलॉजी विभाग के निदेशक डा. अमिताव सेन गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि समय से बहुत पहले जन्में बच्चों के कई ऑर्गन सिस्टम में जटिलताएं हो सकती हैं। क्योंकि उनके अंग अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं।

इस बच्ची निक्की के केस में भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहयोग करते हुए सांस लेने में गंभीर समस्या, इंफेक्शन, सकुर्लेटरी इनस्टेबिलिटी, कोएगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज और पल्मोनरी हैमरेज का उपचार करना पड़ा। डा. अमिताव के अनुसार, हमारा फोकस ना केवल बच्चे को इस क्रिटिकल फेज से बचाना था, बल्कि उसके डेवलप हो रहे ब्रेन को सुरक्षित करना था। क्रिटिकल केयर के साथ-साथ पोषण का भी ध्यान रखा गया। करीब आठ सप्ताह की इंटेसिव नियोनेटल केयर के बाद निक्की को डिस्चार्ज करने का फैसला लिया गया। निक्की के नीकू में रहने के दौरान ऑक्टोपस थेरेपी का भी इस्तेमाल किया गया। एक नरम सूरत से बने ऑक्टोपस को उसकी मां के पास रखने के बाद इनक्यूबेटर में उसके पास रखा गया, ताकि उसमें उसकी जानी-पहचानी खुशबू रहे। बच्ची के माता-पिता ने कहा कि बच्ची को जो देखभाल और ध्यान मिला, उससे उन्हें हिम्मत मिली। हर छोटा सा सुधार उन्हें बड़ी सफलता नजर आया। दो महीने बाद बेटी को घर लाना परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन रहा। उन्होंने डाक्टर्स की टीम का आभार जताया।

आठ सप्ताह तक निकू में इलाज के बाद बच्ची का वजन हुआ 2.64 किलोग्राम

कांशीराम की पुण्यतिथि पर जींद में गूंजा बहुजन मिशन का संकल्प

संविधान, लोकतंत्र और वोट के अधिकार की रक्षा के लिए बीएसपी को सत्ता में लाना होगा: रामजी गौतम



कैथल। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम की 20वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को जींद में सफीदों रोड स्थित दीप पैलेस में श्रद्धांजलि एवं विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बीएसपी हरियाणा के जोन नंबर 1, 2 एवं 3 के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएसपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कृष्ण जमालपुर ने की। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कांशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामजी गौतम ने कहा कि साहब कांशीराम ने बहुजन समाज को संगठित कर राजनीतिक शक्ति में बदलने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और पेरियार के विचारों को जन-जन तक पहुंचाया। बामसेफ, डीएस-4 और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उन्होंने कैडर आधारित आंदोलन खड़ा किया और बहुजन समाज को सत्ता में भागीदारी हासिल करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने गांव-गांव जाकर संगठन मजबूत किया और हजारों कार्यकताओं को तैयार किया। उन्होंने बहन मायावती को नेतृत्व सौंपकर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज उनके विचारों और मिशन को मजबूत करना समय की जरूरत है।

रामजी गौतम ने कहा कि वर्तमान समय में संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आरक्षण और मताधिकार की रक्षा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, मजदूरों की स्थिति और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जनता चिंतित है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की राजनीतिक एकता ही उसके अधिकारों की मजबूत गारंटी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कृष्ण जमालपुर ने कहा कि बीएसपी दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने कार्यकताओं से कांशीराम के विचारों और बहुजन मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाने तथा संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए बहुजन समाज को एकजुट होकर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी होगी। कार्यक्रम में कार्यकताओं ने ह्यमान्यवर साहब कांशीराम अमर रहेंह्ण और ह्यबाबा साहेब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूराह्ण के नारे लगाते हुए बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जोन प्रभारी महेंद्र सिंह धानिया, एडवोकेट नेतराम, महेंद्र जजोरिया, प्रदेश महासचिव रामसिंह प्रजापति, डॉ. मनोज ग्रोवर, प्रदेश सचिव सुरत सिंह, लोकसभा प्रभारी जिले सिंह कश्यप, जींद जिला अध्यक्ष राकेश सिवानामाल, रणधीर घोघड़ियां, पंडित नरेश गौतम, पवन ठाकुर, राजेश सिंघाना, रजत कलोदा और सतबीर निडानी सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना नेता की हत्या के आरोपी यूपी के प्रयागराज से दबोचे गए

प्रयागराज (एजेंसी)। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना (यूबीटी) नेता और पूर्व विभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या के मामले में वांछित दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों को नैनी के अरैल सेल्फी प्वाइंट के पास से पकड़ा गया। आरोपियों की पहचान वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र निवासी संतोष कनौजिया और अमित सिंह के रूप में हुई है। वारदात के बाद दोनों महाराष्ट्र से भागकर प्रयागराज आ गए थे। एसटीएफ के मुताबिक, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कापुरबावड़ी थाने में दर्ज हत्या के मामले में संतोष कनौजिया और अमित सिंह वांछित थे। महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ से सहयोग मांगा था। इसके बाद एसटीएफ की प्रयागराज इकाई ने आरोपियों की तलाश शुरू की। एसीपी शैलेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण और प्रभारी जय प्रकाश राय के नेतृत्व में गठित टीम ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ शुक्रवार रात करीब 7:30 बजे नैनी स्थित अरैल सेल्फी प्वाइंट के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

इंदौर के थाने में भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप, थाना प्रभारी सहित सात पुलिसकर्मी निलंबित

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर शहर के एरोड्रम थाने में भाजपा कार्यकर्ता जयदीप दुबे और उनके जीजा पंकज चौबे के साथ मारपीट और घसीटने का मामला आया है। घटना से नाराज विधायक गोलू शुक्ला के 400 से अधिक समर्थकों ने देर रात थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। हंगामे के बाद थाना प्रभारी वेदेंद्र सिंह कुशवाह सहित सात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। जयदीप दुबे के मुताबिक, शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे घर के पास स्कूटी सवार से अचानक ब्रेक लगाने की बात पर विवाद हुआ था। आरोप है कि स्कूटी सवार ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। बीच-बचाव करने आए उनकी पत्नी और बच्चों के साथ भी अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद वह शिकायत दर्ज करने थाने पहुंचे। दुबे का आरोप है कि सीने में दर्द होने की जानकारी देने के बावजूद उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। रात करीब 11 बजे वह अपने जीजा पंकज चौबे के साथ फिर थाने पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मियों से विवाद हुआ। दुबे ने थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों पर लात-घूंसों तथा डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया। उनकी पत्नी रानू दुबे ने भी पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने और धक्का देने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक गोलू शुक्ला के समर्थक थाने पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। देर रात वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद थाना प्रभारी सहित सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

राजौरी में हादसा : खाई में गिरा वाहन, एक ही परिवार के 30 लोग सवार, दो की मौत, 21 घायल

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के कम से कम दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और 21 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यात्रियों से भरा एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वाहन में एक ही परिवार के लगभग 30 सदस्य सवार थे। यह दर्दनाक हादसा राजौरी जिले के कालाकोट उपमंडल के मोगला-तारयाठ क्षेत्र के केरी छब्बर इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक, सुंदरबनी उपमंडल के मार्चोला इलाके से ये सभी अपने एक रिश्तेदार के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद मोगला-तारयाठ की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान केरी छब्बर इलाके में वाहन चालक कथित तौर पर वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते यह भीषण दुर्घटना हुई। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और बचाव दल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया गया। घायलों को खाई से बाहर निकालने और उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों में दो लोगों की मौके पर मौत और 21 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, हताहतों की अंतिम संख्या और घायलों की स्थिति के संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। समाचार लिखे जाने तक बचाव अभियान जारी था और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही थी।

नागौर में पुजारी से मारपीट के विरोध में हाईवे जाम, 60-70 ग्रामीणों पर मामला दर्ज

नागौर(एजेंसी)। राजस्थान के नागौर जिले में एक पुजारी से मारपीट की घटना के विरोध में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 458 पर जाम लगा दिया। 8 अक्टूबर की रात तपोवन आश्रम घड़वा नाडा के पुजारी के साथ हुई इस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर करीब 60 से 70 ग्रामीणों ने दो घंटे तक हाईवे बाधित रखा, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बेरासर, उबासी और पिंडियां गांवों के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 458 को जाम कर दिया, जिससे नागौर से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और यातायात लगभग दो घंटे तक ठप रहा।

अगर आंदोलन शांतिपूर्ण था, तो सीजेपी नेताओं को हिरासत में लेने की जरूरत क्यों पड़ी

एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने सरकार की कार्रवाई को कायरतापूर्ण बताया

मुंबई, एजेंसी।
एक कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने दीपके और सीजेपी के नेताओं को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है, उन्होंने कहा कि ये नेता दिल्ली में शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। सुले ने सरकार की कार्रवाई को कायरतापूर्ण बताया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर आंदोलन शांतिपूर्ण था, तो नेताओं को हिरासत में लेने की जरूरत क्यों पड़ी।



सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार का तर्क है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी, इसी आशंका के चलते धारा 163 लागू की गई और एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया। सुले ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर कोई शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहा है, तो उसे हिरासत में लेने की जरूरत क्या है। आखिर वे क्या कर लेते। सुले ने जंतर-मंतर पर हुए पिछले आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 24 घंटे युवा मौजूद रहते थे, लेकिन न हिंसा हुई और न ही किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्होंने कहा कि वहां महिलाएं और लड़कियां भी अपने घर की तरह सुरक्षित महसूस कर रही थीं, उनके मुताबिक, यह देखकर अच्छा लगा कि नई पीढ़ी अपने विचारों को लेकर स्पष्ट है और आंदोलन किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ था।
सरकार की ओर से यह दलील दी जा रही है कि जुलाई में संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और संसद की कार्यवाही बाधित होने जैसी स्थिति दोबारा न बने, इसलिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं, लेकिन सुप्रिया सुले ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के पास आंदोलनकारियों से बातचीत करने का विकल्प था। उन्होंने सवाल किया कि सरकार की ओर से किसने आंदोलनकारियों से संपर्क करने की कोशिश की। क्या किसी ने विपक्ष या सीजेपी के नेतृत्व से बातचीत की। सुले के मुताबिक अगर सरकार ने आंदोलनकारियों से संवाद किया होता, तो मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार को संवाद करना ही नहीं आता। सुले ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सीजेपी के साथ खड़ी है।

स्टारलिंक विवाद के बीच अंबानी पर भड़के एलन मस्क बताया पीएम

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को मंजूरी न मिलने पर उद्योगपति मुकेश अंबानी पर सीधा निशाना साधा है। मस्क ने अंबानी को भारत का असली बॉस बताया और उन्हें कटाक्ष करते हुए डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी कहकर संबोधित किया। मस्क भारत में स्टारलिंक को मंजूरी न मिलने से पहले से ही बौखलाए हुए हैं। मस्क ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप ही भारत के असली बॉस हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंबानी भारत के लोगों का एकतरफा शोषण करेंगे, लेकिन स्टारलिंक को देश में नहीं आने देंगे। मस्क के अनुसार, भारत के कई इलाकों में इंटरनेट नहीं है, जिससे बहुत सारे छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और छोटे कारोबारी अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच पाते। उन्होंने दावा किया कि स्टारलिंक लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। एक दिन पहले, मस्क ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए पूछा था कि क्या अंबानी ही भारत के असली बॉस हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या भारत सरकार अब नागरिकों के हितों को नजरअंदाज करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली व्यवस्था की रक्षक बन गई है। मस्क ने बताया कि स्टारलिंक को 165 देशों में लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन भारत में सभी शर्तों का पालन करने के बाद भी उसे मंजूरी नहीं मिली है।



वांगचुक का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम, 24 घंटे में नहीं किया रिहा...



नई दिल्ली , एजेंसी।
लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली में हो रहे सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान नेताओं की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए है। उन्होंने भारत को अघोषित आपातकाल की स्थिति में बताकर गिरफ्तार नेताओं को जल्द रिहा करने की मांग की है। पर्यावरण कार्यकर्ता वांगचुक ने साफ कहा है कि अगर इन नेताओं को कल तक रिहा नहीं किया गया, तब वह अनशन या पदयात्रा शुरू करने पर विचार करुंगा। इन नेताओं में अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका सहित कॉकरोच पार्टी के कई लोग शामिल हैं।
वांगचुक ने एक बयान जारी कर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उन्होंने आज के प्रदर्शन को लेकर एकजुटता और शांति बनाए रखने की अपील की थी। तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसी स्थिति बन जाएगी, इस स्थिति को अघोषित आपातकाल मान रहे हैं।
वांगचुक के मुताबिक, उन्हें इसकी खुशी थी कि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कई नेता आगे आए हैं। लेकिन अब उन्हें पता चला है कि उन सभी नेताओं को गिरफ्तार किया है। वांगचुक ने इसी बात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि गिरफ्तार किए गए सभी नेताओं को जल्द रिहा किया जाएगा।
वांगचुक ने साफ किया है कि अगर कल तक नेताओं की रिहाई नहीं होती, तब उन्हें अनशन या पदयात्रा शुरू करने पर विचार करना पड़ेगा। यानी वे खुद अनशन या पदयात्रा के जरिए अपना विरोध दर्ज करने पर सोच सकते हैं। अनशन का मतलब खाना छोड़कर विरोध करना है, जबकि पदयात्रा में लोग पैदल चलकर अपनी बात रखते हैं। वांगचुक ने अपने संदेश में शांति और एकजुटता पर जोर दिया है।

मैं अयोध्या से लड़ने को तैयार, आप भी नामांकन कीजिए...

सीएम योगी को मंजूर अखिलेश का चैलेंज

लखनऊ , एजेंसी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर पलटवार किया है। जनसभा में उन्होंने अखिलेश को भी अयोध्या से नामांकन करने को कहा और माफिया, राम मंदिर और विपक्ष की भाषा पर भी पलटवार किया। उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर सवाल उठा दिए।
अखिलेश दो दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचे थे। जहां उन्होंने भागवत कथा में हिस्सा लिया, संतों से आशीर्वाद लिया और एक जनसभा में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा है,तब अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। उनका कहना था कि राज्य न्याय और मानवता से चलता है और अयोध्या की जनता चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।



अखिलेश की चुनौती पर योगी ने बलरामपुर में सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अखिलेश, अयोध्या हमारी पावन धाम है। हम सियासत के लिए नहीं, विकास के लिए अयोध्या जाते हैं। 'आइए, आपको ऑफर देता हूं। आप भी अयोध्या से नामांकन करिए और मैं भी। चलिए, एक बार अपनी किस्मत आजमा लेते हैं। योगी ने अयोध्या को अपनी आस्था की स्थली बताया।
सीएम योगी ने जनसभा में पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उनका आरोप था कि पहले माफिया जिस जमीन पर पैर रखता था, उस पर कब्जा कर लेता था। सपा के गुंडे व्यापारियों को फोन कर धमकाते और संपत्ति हड़प लेते थे। उन्होंने दावा किया कि 2017 से पहले बलरामपुर की सड़कें सबसे खराब थीं। अब वोट तस्करी और बदमाशों की अराजकता की जगह विकास और बदलाव का आधार बन रहा है और इलाके को आकांक्षात्मक जिले से संभावनाओं वाला जिला बनाने पर काम किया जा रहा है।
सीएम योगी ने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम का जिक्र कर कहा कि इनके निर्माण में रुकावट बनने वाले आज प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं, पर विरोध की भी एक सीमा होती है। कांग्रेस और सहयोगी दलों पर उन्होंने शिष्टाचार भूलने और अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक इसतरह के प्रयास देश को गुमराह करने और अराजकता की ओर ले जाने वाले हैं। इसके पहले डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा था कि अखिलेश भागवत कथा में गए, पर राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। उनके मुताबिक रामलला के दर्शन न करने वालों की रामभक्ति पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि देश और दुनिया से लोग मंदिर पहुंच रहे हैं।

आली धाम में चढ़ा रिकॉर्ड चढ़ावा, 19 लाख से ज़्यादा के नोट मिले

चित्तौड़गढ (एजेंसी)। जिले के कपासन उपखंड स्थित मेवाड़ के सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री शनिमहाराज आली धाम में मंदिर के भंडारे (दानपात्र) खोले गए। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा आस्थापूर्वक अर्पित की गई भेंट राशि की गिनती की गई। केवल नोटों की गिनती में ही कुल 19 लाख 41 हजार 755 रुपये की रिकॉर्ड भेंट राशि प्राप्त हुई है। मंदिर ट्रस्ट और प्रबंध समिति के अनुसार, सिक्कों की गिनती प्रक्रिया अभी जारी है, जिसके बाद ही इस माह प्राप्त हुई कुल भेंट राशि का अंतिम और सटीक आंकड़ा सार्वजनिक किया जा सकेगा। कपासन क्षेत्र के इस प्रमुख धार्मिक स्थल श्री शनिमहाराज आली में हर महीने अमावस्या से ठीक एक दिन पहले चतुर्दशी के पावन अवसर पर मंदिर के दानपात्रों को खोलने की वर्षों पुरानी परंपरा है। शनिवार को भगवान श्री शनिदेव महाराज की विशेष विधि-विधान से पूजा-अर्चना, आरती और मंत्रोच्चार के बाद मुख्य समिति की मौजूदगी में भंडारों को खोला गया। इस दौरान मुख्य मंदिर परिसर, नवग्रह मंदिर और तेल कुंड के पास स्थित दानपात्रों से श्रद्धालुओं द्वारा समर्पित की गई भेंट राशि निकाली गई। दानपात्रों से निकाली गई राशि की गिनती कड़ी सुरक्षा और मंदिर पदाधिकारियों की उपस्थिति में शुरू की गई। बीती रात तक नोटों की गिनती का काम पूरा कर लिया गया, जिसमें यह रिकॉर्ड राशि प्राप्त हुई। इसके बाद अब सिक्कों की छंटनी और गिनती की प्रक्रिया शुरू की गई है। गिनती की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है। चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ क्षेत्र में श्री शनिमहाराज आली धाम की अपार धार्मिक मान्यता है। हर महीने आने वाली अमावस्या पर यहां देश और प्रदेश के विभिन्न कोनों से हजारों-लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शनिदेव के दर्शन करने और तेल चढ़ाने पहुंचते हैं। भक्तों में मान्यता है कि यहां तेल अर्पण करने और पूजा-अर्चना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी अपार आस्था के चलते हर महीने भंडारे में लाखों रुपये की भेंट राशि और तेल समर्पित किया जाता है।

'हिरासत में हूं, लेकिन आंदोलन जारी है, हिरासत में ली गईं आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा

नई दिल्ली, एजेंसी।
नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले पुलिस ने आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लेकर पुलिस अपने साथ ले गई। प्रदर्शन को देखकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हिरासत में लेने के बाद नेहा बोरा ने कहा, 'मैं हिरासत में हूं, लेकिन आंदोलन जारी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सफदरजंग फ्लाईओवर पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी को रोका जाता है, तब वह उसी स्थान पर बैठकर विरोध जारी रखे। आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा ने श्री अरबिंदो मार्ग और सफदरजंग के पास हिरासत में लिए गए लोगों का जिक्र कर कहा कि एक बस में उनके कई साथी मौजूद हैं और उसके आसपास हजारों प्रदर्शनकारी जुटे हैं। उन्होंने लोगों से उसी जगह पहुंचकर प्रदर्शन शुरू करने की अपील की, जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया था।



प्रदर्शन के बीच शनिवार सुबह से दिल्ली में करीब दो हजार लोगों को एहतियातन हिरासत में लेने की जानकारी सामने आई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी लोदी एस्टेट के बाहर से हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। वहीं, पूर्व सांसद साकेत गोखले ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पांच अन्य नेताओं को उनके दिल्ली स्थित आवास के बाहर से हिरासत में लिया गया। गोखले के अनुसार, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल उन्हें एक वाहन में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए। यह पूरा घटनाक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान सामने आया।
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली को बाधित करने और हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अराजकतावादी नाकाम रहे और इस कार्रवाई को भीड़तंत्र पर लोकतंत्र की जीत बताया। बीजेपी नेता पात्रा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधकर आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर दोनों दल आंदोलन का नेतृत्व करने का श्रेय लेने की होड़ में हैं।

किश्तवाड़ आतंकी हमला : एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट

पाकिस्तान में बैठे आतंकी दे रहे थे निर्देश

जम्मू, एजेंसी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने किश्तवाड़ के छत्रू क्षेत्र में हुए आतंकी हमले की गहन जांच के बाद शुक्रवार को एक विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया है। इस आरोपपत्र में यह बड़ा खुलासा किया गया है कि हमले की पूरी साजिश सीमा पार पाकिस्तान में रची गई थी। जम्मू स्थित ह्द्द की विशेष अदालत में दायर किए गए 535 पन्नों के इस दस्तावेज में गिरफ्तार आरोपी मनीर अहमद और सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए तीन पाकिस्तानी आतंकियों को नामजद किया गया है। जांच ने स्पष्ट कर दिया है कि इस आतंकी वारदात की कमान प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी कमांडर सैफुल्ला के हाथों में थी।
यह मामला 22 फरवरी 2026 का है, जब किश्तवाड़ जिले के छत्रू क्षेत्र के वानी मोहल्ला, पासेर कोटे में आतंकियों ने सुरक्षा व्यवस्था को निशाना बनाते हुए हमला किया था। एनआईए ने लगभग पांच महीने की व्यापक और गहन जांच के बाद हमले की साजिश के हर पहलू, आतंकियों की भूमिका और उन्हें स्थानीय स्तर पर मिली मदद के स्रोतों की पड़ताल की। आरोपपत्र के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी मनीर अहमद पर आतंकियों को अपने घर में शरण देने और छिपाने का गंभीर आरोप है, जिसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। वहीं, मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों पर भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और आपराधिक साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।जांच एजेंसी ने बताया कि हमले में शामिल तीनों आतंकियों का नेतृत्व पाकिस्तानी नागरिक सैफुल्ला कर रहा था, जो जैश-ए-मोहम्मद का एक सक्रिय कमांडर था। उसे सैफुल्ला कश्मीरी, अतीक नजीर और अतीक उर रहमान जैसे कई उपनामों से भी जाना जाता था और वह जैश से जुड़े कश्मीर टाइगर्स (अजरैल ग्रुप) का सदस्य था।

महाराष्ट्र में सूखे का गहरा संकट: किसानों को जल संरक्षण और फसल प्रबंधन पर जोर -- राष्ट्रीय में जारी करना हैं

मुंबई, एजेंसी।
महाराष्ट्र में सूखे का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे महाराष्ट्र के किसान लगातार चिंतित हैं। कमजोर और असमान मॉनसून के कारण राज्य के 358 में से 265 तालुके सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। खरीफ फसलों को हुए नुकसान के बाद अब रबी सीजन की चिंता भी सता रही है। इसके बाद किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उपलब्ध पानी को बचाना और अगली फसल को सूखे की मार से सुरक्षित रखना है।
इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 16 अक्टूबर से करीब 10 प्रतिशत पानी की कटौती करने का निर्देश दिया है। जल संसाधन विभाग ने बांधों में उपलब्ध पानी की योजना अगस्त 2027 तक के लिए बनाई है, जिसमें आपातकालीन पानी का बफर स्टॉक भी शामिल है। महायुति सरकार ने पानी के इस्तेमाल की प्राथमिकताएं भी तय की हैं। पहले पीने का पानी, फिर पशुओं और चारे के लिए पानी, और अंत में सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। इसके बाद किसानों को रबी की फसल चुनते समय पानी की कमी को गंभीरता से लेना होगा।
किसानों को अपने क्षेत्र की मिट्टी, उपलब्ध नमी और पानी के स्रोत को ध्यान में रखते हुए फसलों का चुनाव करना चाहिए। सूखे की स्थिति में, कम समय और कम पानी में तैयार होने वाली फसलें अधिक उपयुक्त होंगी। साथ ही, खेत की मिट्टी में मौजूद नमी को बचाने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ सिंचाई की जरूरत हो, वहाँ ड्रिप या माइक्रो-इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर पानी की बचत की जा सकती है। फसल नुकसान से प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने 265 सूखाग्रस्त तालुकों में आकलन शुरू किया है। 12 अक्टूबर तक पंचनामे पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि प्रभावित किसानों तक सहायता मिल सके। किसानों को अपने गाँव में होने वाले पंचनामे की जानकारी लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी फसल का नुकसान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो। इसके अतिरिक्त, सूखा से प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अन्य सरकारी राहत प्रक्रियाओं की जानकारी अपने तहसील कार्यालय या कृषि विभाग से तुरंत प्राप्त करनी चाहिए। केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना में सूखा सहित कई प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ कवरेज उपलब्ध है। महाराष्ट्र राज्य में हरे और सूखे चारे की कमी की रिपोर्ट भी सामने आई है। किसानों को उपलब्ध चारे का भंडारण करना चाहिए और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था पर पहले से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने पेयजल के बाद पशुधन और चारे को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इन उपायों को अपनाकर किसान इस संकट की घड़ी में खुद को और अपनी आजीविका को सुरक्षित रख सकते हैं।



नारी का सम्मान और स्वावलंबन ही राम राज्य का आधार: योगी आदित्यनाथ

योगेश कुमार

बलरामपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी को सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन मिलेगा तो राम राज्य की स्थापना को कोई ताकत नहीं रोक सकती। मां भगवती की आराधना का वास्तविक अर्थ भी यही है कि समाज हर महिला के सम्मान व सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में हर पांचवीं बेटी स्कूल में दाखिला लेने के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती थी। स्कूलों में शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाएं नहीं थीं। आज प्रदेश के 1.60 करोड़ बच्चों को हर साल दो यूनिफॉर्म, बैग, पुस्तकें, स्वेटर और जूते-मोजे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बेटियों की शिक्षा और महिलाओं का स्वावलंबन हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री रविवार को देवीपाटन मंदिर प्रांगण में शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित 'शिक्षा की उड़ान' पहल के तहत स्टडी टेबल एवं आशीर्वाद पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवदुर्गा स्वरूप नौ कन्याओं का तिलक किया, चुनरी ओढ़ाई और चॉकलेट भेंट की। बेटियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति



में नारी शक्ति की उपासना की परंपरा रही है। नवरात्रि इसी संकल्प को मजबूत करने का अवसर है।

न्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं और विजयदशमी पर भगवान राम के विजय उत्सव को भव्यता से मनाने का आह्वान किया।

स्कूल छोड़ने वाली बेटियों की जांच कराई तो सामने आई हकीकत

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद उन्होंने बी संख्या में बेटियों के स्कूल छोड़ने की वजह पूछी। पहले विद्यालयों की दूरी को कारण बताया गया। जांच के लिए टीम गठित की तो सामने आया कि स्कूलों में शौचालय और पेयजल तक की व्यवस्था नहीं थी।

अहिल्याबाई से लक्ष्मीबाई तक नारी शक्ति के उदाहरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि माता कौशल्या, जानकी, शबरी, देवकी, यशोदा, द्रौपदी, मैत्रेयी और गार्गी भारतीय नारी के सामर्थ्य की प्रतीक हैं। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और केदारनाथ सहित अनेक मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। रानी लक्ष्मीबाई ने 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और 26 वर्ष में बलिदान हो गईं। अवंतीबाई लोधी, ऊदा देवी पासी और झलकारी बाई ने भी देश के लिए संघर्ष किया। भारत में संविधान निर्माण के साथ ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर मतदान का अधिकार मिला।

फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन, किसानों को सौंपे उपकरण

मुख्यमंत्री योगी ने फीता काटकर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कृषि, उद्यान, रेशम विकास, पराग मिल्क और कृषि विज्ञान केंद्र के स्टालों का अवलोकन किया। विराट किसान मेले में कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत किसानों को चाबियां सौंपीं और कीटनाशक छिड़काव यंत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना पूरी हो चुकी है।

जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में चार घरों के ताले टूटे, लाखों की चोरी का आरोप

मनोज सिंह



गुरुग्राम/मोहम्मदपुर (सत्यम् लाइव): हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मोहम्मदपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत के अनुसार, एक ही रात में परिसर के चार घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपये के आभूषण और नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता की ओर से चोरी हुए सामान की कुल कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक होने का दावा किया गया है। हालांकि, चोरी की कुल रकम और संपत्ति के मूल्य की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं हो सकी है।

चार घरों के ताले तोड़ने का आरोप: उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चोरी की घटना 2 सितंबर 2026 की रात हुई। आरोप है कि जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में स्थित चार घरों को निशाना बनाया गया और उनके ताले तोड़कर आभूषण एवं नकदी चोरी कर ली गई। घटना के बाद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता पक्ष ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

FIR दर्ज होने में देरी का आरोप

पीड़ित मुन्ना कुमार सिंह की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, चोरी की घटना 2 सितंबर की रात हुई थी, जबकि **FIR** 7 सितंबर 2026 की रात दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि **FIR** में करीब दो लाख रुपये की नकदी का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

इस संबंध में **FIR** की वास्तविक सामग्री और पुलिस की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण उपलब्ध होने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और चोरी की घटना के बाद अपेक्षित कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने मामले की गंभीरता से जांच कराने, चोरी हुए सामान का पता लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग

मामले को लेकर शिकायतकर्ता पक्ष ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे परिसर की सुरक्षा में हुई कथित चूक की जांच होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

रामलीला भी चलेगी, दिल्ली भी चलती रहेगी: ट्रैफिक पुलिस



योगेश कुमार सोनी

पूर्वी दिल्ली (सत्यम् लाइव) : राजधानी दिल्ली में रामलीला आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, जोन-1 की ओर से रामलीला समितियों के पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक दिल्ली पुलिस जीओज मेस, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस/ट्रैफिक, डीसीपी ईस्टर्न रेंज, डीसीपी सेंट्रल रेंज, जोन-1 के सभी एसीपी ट्रैफिक, ट्रैफिक इंस्पेक्टर तथा विभिन्न रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

उप्र में जीत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी बधाई: बैठक का मुख्य उद्देश्य रामलीला आयोजकों और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर त्योहारों के दौरान सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करना था, ताकि श्रद्धालुओं और दर्शकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और राजधानी में सामान्य यातायात भी प्रभावित न हो।

रामलीला भी चलेगी, दिल्ली भी चलती रहेगी: बैठक को संबोधित करते हुए एडिशनल सीपी/ट्रैफिक ने स्पष्ट संदेश दिया कि रामलीला का आयोजन पूरे उत्साह और भव्यता के साथ होगा, लेकिन इसके साथ दिल्ली की रफ्तार भी नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के कारण दैनिक यात्रियों, स्थानीय निवासियों, आपातकालीन सेवाओं और आम जनता को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आयोजकों को पहले से यातायात पुलिस के साथ समन्वय कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। उन्होंने कहा, रामलीला भी चलेगी, दिल्ली भी चलती रहेगी। इसके लिए अग्रिम ट्रैफिक प्लानिंग, पार्किंग व्यवस्था, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इन व्यवस्थाओं पर रहा विशेष जोर: बैठक में रामलीला स्थलों के आसपास यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रमुख सड़कों और जंक्शनों पर यातायात का निर्बाध संचालन, व्यवस्थित पार्किंग, अवैध एवं सड़क पर बेतरतीब पार्किंग की रोकथाम तथा दर्शकों के सुरक्षित प्रवेश और निकास पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। आवश्यकता पड़ने पर पहले से ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों की योजना तैयार करने तथा एंबुलेंस, दमकल और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ते खुले रखने पर भी जोर दिया गया। रामलीला समितियों से पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों की तैनाती करने की अपील की गई, ताकि पार्किंग व्यवस्था, पैदल यात्रियों के मार्गदर्शन और आम जनता की सुविधा में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग किया जा सके।

सीबीडी ग्राउंड में भव्य रामलीला की तैयारी पूरी, 10 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था

अनिल सिंह चौहान



नई दिल्ली (सत्यम् लाइव) : नई दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड, क्रॉस रिवर मॉल के सामने बालाजी रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित होने वाली 16वें वर्ष की भव्य रामलीला की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मयार्दा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की लीला को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस रामलीला में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कमेटी के अनुसार, रामलीला के लिए करीब 25 हजार वर्गफुट क्षेत्र में विशाल पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 10 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

तीन ब्लॉक में बनाया गया पंडाल: दर्शकों को मंच का स्पष्ट दृश्य मिल सके, इसके लिए पंडाल को तीन ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन ब्लॉकों को चरणबद्ध तरीके से ऊंचा रखा गया है, ताकि पीछे बैठे दर्शकों को भी मंच दिखाई दे सके। रामलीला के प्रमुख आकर्षणों में दशानन रावण का भव्य मंच प्रवेश शामिल रहेगा।

युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए झूलों की व्यवस्था

रामलीला परिसर में युवा पीढ़ी और बच्चों को आकर्षित करने के लिए



विभिन्न मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। परिसर में गगनचुंबी झूले और जीरो ग्रेविटी झूले लगाए जा रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि धार्मिक आयोजन के साथ मनोरंजन की सुविधाओं के माध्यम से युवाओं और परिवारों को भी रामलीला से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान

बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई है। परिसर में 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती रहेगी। भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने के लिए प्रवेश और निकास की अलग व्यवस्था की गई है।

दो प्रवेश द्वार और एक इमरजेंसी एग्जिट: आयोजकों के अनुसार, दर्शकों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने के लिए दो प्रवेश द्वार और एक इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दर्शकों के वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। कमेटी की ओर से रामलीला के दौरान सुरक्षा, दर्शकों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी करने की बात कही गई है।

सलवान पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता सत्र, 150 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

योगेश कुमार सोनी



पूर्वी दिल्ली (सत्यम् लाइव) : सड़क सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज मयूर विहार फेज-3 स्थित सलवान पब्लिक स्कूल, प्रगति मार्ग में सड़क सुरक्षा जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कल्याणपुरी ट्रैफिक सर्किल के स्टाफ और सलवान पब्लिक स्कूल के संयुक्त सहयोग से किया गया। जागरूकता सत्र में करीब 150 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विद्यार्थियों को सुरक्षित सड़क पार करने, जिम्मेदारी के साथ साइकिल चलाने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने और सड़क पर सुरक्षित व्यवहार अपनाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रति भी किया जागरूक: विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि वे अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने तथा कार में यात्रा करते समय सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित करें। अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी अच्छी आदतें बचपन से विकसित होने पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

विद्यार्थियों के साथ हुआ इंटरैक्टिव सत्र: जागरूकता कार्यक्रम के बाद सड़क सुरक्षा विषय पर एक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने यातायात नियमों और सुरक्षित सड़क व्यवहार से जुड़े सवालों पर चर्चा की। इस संवादात्मक गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों की सड़क सुरक्षा संबंधी समझ को और मजबूत करना तथा उन्हें जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना था।

परिवार और समाज को जागरूक करने का संदेश: कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों का स्वयं पालन करने के साथ-साथ अपने परिवार और समाज के लोगों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सुरक्षित सड़क व्यवहार अपनाने और यातायात नियमों का जिम्मेदारी के साथ पालन करने के महत्व से अवगत कराया गया।

मुख्यमंत्री सम्राट ने पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण का दिया निर्देश



पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को नेहरू पथ पर चल रहे पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इनकम टैक्स गोलंबर, हाई कोर्ट चौराहा एवं हनुमान मंदिर के समीप पहुंचकर निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों से कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2028 तक पूर्ण करें। परियोजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने कहा कि जेडी विमेंस कॉलेज तथा हाईकोर्ट चौराहा-बिहार म्यूजियम के पास नेहरू पथ पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण करायें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए व्यवस्थित एवं समन्वित तरीके से कार्य किया जाए। निर्माण स्थलों के आसपास यातायात प्रबंधन, आवागमन की सुगमता तथा नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर उन्होंने जोर दिया।

नन्ही की हिम्मत और इंसानियत की मिसाल, गांधी नगर मार्केट में दिखी मानवता

योगेश कुमार सोनी



पूर्वी दिल्ली (सत्यम् लाइव): दिल्ली के गांधी नगर स्थित सुभाष रोड मार्केट में इंसानियत और संवेदनशीलता की एक ऐसी मिसाल सामने आई, जिसने यह दिखाया कि मुश्किल समय में यदि लोग मदद के लिए आगे आएं तो किसी जरूरतमंद की परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एटा के डुमरी गांव की रहने वाली नन्ही घरेलू हिंसा और आर्थिक परेशानियों के बावजूद अपने बच्चों और परिवार का जीवन संभालने तथा आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही हैं। उनके पास अपना मकान नहीं है और आय का भी कोई स्थायी साधन नहीं है। उनके अनुसार, पति की ओर से भी उन्हें सहयोग के बजाय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

उधार लेकर परिवार का सामान खरीदने पहुंचीं गांधी नगर: परिस्थितियों के सामने हार न मानते हुए नन्ही ने अपने पड़ोस से कुछ पैसे उधार लिए और परिवार के लिए आवश्यक सामान खरीदने गांधी नगर की सुभाष रोड मार्केट पहुंचीं। सुबह करीब सात बजे मार्केट पूरी तरह खुली भी नहीं थी। उन्होंने कुछ दुकानों से सामान खरीदा और एक दुकान पर अपना सामान रख दिया, ताकि आगे की दुकानों से खरीदारी करने के बाद सभी सामान को एक साथ ले जा सकें। लेकिन कुछ देर बाद जब पूरी मार्केट खुली और नन्ही सामान लेने वापस पहुंचीं तो उन्हें याद नहीं रहा कि उन्होंने अपना सामान किस दुकान पर रखा था।

अजनबी शहर में सामान तलाशती रहीं नन्ही: अजनबी शहर, सीमित पैसे और सामने खड़ी परेशानी ने नन्ही की मुश्किल बढ़ा दी। वह रोते हुए पूरी मार्केट में अपने सामान और उस दुकान को तलाशती रहीं, जहां उन्होंने अपना सामान रखा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात मनोज उपाध्याय, संजय शर्मा और प्रशांत तिवारी से हुई। तीनों ने उनकी परेशानी को समझते हुए मदद शुरू की। आसपास की दुकानों में सामान तलाशने के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी संपर्क किया गया, लेकिन पहले दिन सामान का पता नहीं चल सका। नन्ही के पास रात में ठहरने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में उनके रुकने की व्यवस्था भी की गई।

राजवीर सिंह को दी गई मामले की जानकारी: मामले की जानकारी प्रशांत तिवारी ने एटा से भाजपा सांसद प्रत्याशी रहे राजवीर सिंह को दी। उन्होंने भी नन्ही की हरसंभव मदद का आश्वासन दिया और इस मानवीय पहल की सराहना की। उधर, गांधी नगर थाना अध्यक्ष राज कुमार और उनकी टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सामान की तलाश के प्रयास जारी रखे। टीम में विशेष रूप से विकास यादव, वीरेंद्र सिंह और अन्य सहयोगियों ने नन्ही की मदद के लिए संवेदनशीलता के साथ काम किया।

दूसरे दिन मिली सामान से भरी बैग

दूसरे दिन सुबह करीब सात बजे पुलिस और मददगारों ने नन्ही को उन्हीं गलियों और दुकानों में दोबारा ले जाकर तलाश शुरू की, जहां उन्होंने पिछली सुबह खरीदारी की थी। लगातार प्रयास के बाद आखिरकार नन्ही का बैग और खरीदा हुआ सामान मिल गया। संबंधित दुकानदार ने सामान को सुरक्षित संभालकर रखा था और नन्ही के वापस आने का इंतजार कर रहा था।

बेटी की शादी के लिए व्यापारियों ने दिया अतिरिक्त सामान: सामान मिलने के बाद भी मदद का सिलसिला यहीं नहीं रुका। गांधी नगर के व्यापारियों मनोज उपाध्याय, संजय शर्मा, प्रशांत गोयल, गोविंद सिंघल, दीपक गुप्ता, अंकुर छतवाल, अंकित गुप्ता, ओम प्रकाश, संजय सक्सेना सहित अन्य लोगों ने प्रशांत तिवारी की अगुवाई में नन्ही को उनके खरीदे हुए सामान के साथ अतिरिक्त सामान भी भेंट किया। बताया गया कि करीब दो महीने बाद नन्ही की बेटी की शादी होनी है। व्यापारियों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी ओर से सहयोग किया, ताकि नन्ही अपने घर लौटकर परिवार का पालन-पोषण करने के साथ बेटी की शादी की जिम्मेदारी भी निभा सकें।

पुलिस ने सुरक्षित बस में बैठाकर किया विदा: दो दिनों तक दिल्ली जैसे अनजान शहर में परेशान रहीं नन्ही को आखिरकार गांधी नगर थाना अध्यक्ष राज कुमार ने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर उनके शहर वापस जाने वाली बस में सुरक्षित बैठाया। उन्हें बड़े भाई की तरह भरोसा और सहयोग देते हुए विदा किया गया।

नन्ही की हिम्मत और समाज की संवेदनशीलता बनी मिसाल: यह घटना केवल खोए हुए सामान के मिलने की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी महिला की हिम्मत की कहानी है, जिसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी। यह उन लोगों की मानवता की कहानी भी है, जिन्होंने एक अनजान महिला की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। साथ ही, यह गांधी नगर के व्यापारियों की सहृदयता और पुलिस प्रशासन की संवेदनशील भूमिका को भी सामने लाती है। नन्ही ने हार नहीं मानी और इंसानियत ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। मुश्किल समय में यदि इंसान दूसरे इंसान के साथ खड़ा हो जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी पड़ सकती है।

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना जारी, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग

शरद शर्मा



आगरा (सत्यम् लाइव) : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आगरा में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय परिसर में धरना जारी है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करने की तैयारी की है। कार्यक्रम प्रबंधक संघ उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष राहुल भारद्वाज के अनुसार, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले आगरा में 8 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को भी धरना जारी रहा, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य संवर्गों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

समान कार्य-समान वेतन और नियमितीकरण की मांग: कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवाओं का नियमितीकरण शामिल है।

प्रदर्शन में डॉक्टर, एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और अन्य संवर्गों के कर्मचारी शामिल रहे। ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक, बीपीएम यूनिट और अन्य कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हुए। कर्मचारी संगठन का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर समाधान के लिए सरकार के सामने अपनी बात रखी जा रही है।

लखनऊ में 12 अक्टूबर को जुटने की तैयारी: राहुल भारद्वाज के अनुसार, आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्तर पर आगे बढ़ाने की योजना है। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के ईको गार्डन में प्रदेशभर के संविदा कर्मचारियों के एकत्र होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आयोजकों ने इस प्रदर्शन में डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारियों के पहुंचने की आशंका जताई है। यह संख्या आयोजकों का अनुमान है; वास्तविक भागीदारी की पुष्टि कार्यक्रम के दौरान ही हो सकेगी।

कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी धरने में शामिल: आगरा में जारी धरने में जिला अध्यक्ष देवी कुशवाह, महामंत्री दामोदर सिंह, भारतीय मजदूर संघ के जिला संयोजक कुलदीप सिंह राणा, तहसील प्रभारी लोकेन्द्र तिवारी, सत्येंद्र कुमार, जगन्नाथ शर्मा, राजेश सिकरवार, डॉ. कपिल और डॉ. संजीव महेश्वरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समाधान की मांग उठाई और संगठन के माध्यम से आंदोलन जारी रखने की बात कही।

प्रदेशभर में जारी है आंदोलन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भी प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लखनऊ के ईको गार्डन में भी NHM कर्मचारियों ने नियमितीकरण और समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक योगेश कुमार द्वारा 4649/89/1, गली न.– 3, न्यू मॉडर्न शाहदरा, दिल्ली–110032 से प्रकाशित तथा लक्ष्य प्रिंटर्स, 521/8B, ग्राउंड फ्लोर, गली नंबर–14, आदर्श मोहल्ला, मौजपुर दिल्ली–110053 से मुद्रित। संपादक : योगेश कुमार, कार्यालय : 011–49937046, मोबाइल : 7503000220, R.N.I. No. : DELHIN/2011/36763,
(समाचार पत्र संबंधी वाद–विवाद का न्याय क्षेत्र दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगा।)